● वर्ष-4
● अंक-179
रायपुर, शुक्रवार
07 मार्च 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» डायबिटीज और गठिया रोगी आज से....

3 दिन में 3 अफसर सस्पेंड

एक्शन में विष्णुदेव सरकार, भारतीय वन सेवा के एक अफसर समेत राज्य सेवा के दो अफसर निलंबित...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए तीन दिन में तीन अफसरों को सस्पेंड कर दिया। इनमें भारतीय वन सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं।

2015 बैच के आईएफएस अधिकारी अशोक पटेल सुकमा के डीएफओ के साथ लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक थे। आदिवासियों को तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि की गड़बड़ियों में उन्हें निलंबित किया गया है। प्रारंभिक जांच में डीएफओ की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी।

अशोक पटले ऑल इंडिया सर्विस के अफसर हैं। डीएफओ रैंक के अफसर को सस्पेंड करना बड़ी कार्रवाई मानी जाती है। रमन सरकार की तीसरी पारी में राजेश चंदेले के बाद अशोक पटेल पहले आईएफएस होंगे, जिन्हें सस्पेंड किया गया है।

3 मार्च को डीएफओ को सस्पेंड करने के अगले दिन 4 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार ने जगदलपुर नग निगम के कमिश्नर निर्भय साहू को निलंबित किया। निर्भय साहू को अभनपुर में एसडीएम रहते भारतमाला परियोजना के 324 करोड़ के मुआवाजा घोटाला में सस्पेंड किया गया। रायपुर से विशाखापट्टनम सिक्स लेन कारिडोर के लिए जमीन अधिग्रहित करने के दौरान एसडीएम ने 35 करोड़ की जगह 246 करोड़ का मुआवजा बांट दिया। इसके लिए 32 खसरे को 247 छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया।

एसडीएम निर्भय साहू को निलंबित करने के बाद 5 मार्च को सरकार ने कोरबा के डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे को सस्पेंड कर दिया। शशिकांत के खिलाफ भी भारतमाला परियोजना में मुआवजे के बंदरबांट को लेकर कार्रवाई की गई है। अभनपुर के तहसीलदार रहते हुए शशिकांत ने मुआवजा स्कैम में मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई।

रायपुर कलेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार शशिकांत ने ही भारत सरकार की परियोजना में करोड़ों 300 करोड़ का वारा-न्यारा करने के लिए प्रतिबंध के बावजूद जमीनों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल दिया ताकि आठ गुना मुआवजा दिलाया जा सके। इसकी एवज में राजस्व अधिकारियों को मोटा कमीशन मिला।

बता दें, अभनपुर के भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले में इससे पहले एक तहसीलदार और दो पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है। याने इस मामले में अभी तक राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों समेत पांच को सस्पेंड किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के बजट सत्र में एक सवाल के जवाब में कहा था कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, गड़बड़ी में लिप्त किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

ज्ञातव्य है, तीन दिन में तीन अफसर, सस्पेंड हुए हैं, उनमें से एक ऑल इंडिया सर्विस और दो राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं। इन तीनों सर्विस मुख्यमंत्री के अधीन होती हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी मंत्री की नोटशीट की जरूरत नहीं पड़ती। वरना, विभागीय मंत्री इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। 25 मार्च को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अभनपुर मुआवजा घोटाले के लिए प्रश्नकाल में सवाल पूछा था कि कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में किसके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है तो राजस्व मंत्री का टका सा जवाब आया था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि, रायपुर कलेक्टर महीने भर पहले जांच रिपोर्ट राजस्व विभाग को भेज चुके थे।

उत्तराखंड विंटर टूरिज्म को मोदी ने किया प्रमोट

उत्तराखंड/नईदिल्ली। एक दिवसीय शीतकालीन यात्रा पर उत्तरकाशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुखवा और हर्षिल से उत्तराखंड में शीतकालीन तीर्थाटन और पर्यटन की जोरदार ब्रांडिंग की।

प्रधानमंत्री ने तीर्थयात्रियों, पर्यटकों से लेकर कॉरपोरेट और फिल्म उद्योग तक को विंटर सीजन में उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म की 'घाम तापो टूरिज्म' के तौर पर ब्रांडिंग की है।

गुरुवार को हर्षिल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले बीते दिनों माणा में हुए हिमस्खलन में दिवंगत लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया।

इसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की यह भूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड से अपना आत्मीय लगाव व्यक्त करते हुए कहा कि वो जीवनदायनी मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर अपने परिवारजनों के बीच पहुंचकर धन्य महसूस कर रहे हैं। मां गंगा की कृपा से ही उन्हें दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला। मां गंगा के आशीर्वाद से ही वो काशी पहुंचकर सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने ही उन्हें काशी बुलाया है।प्रधानमंत्री मोदी ने दार्शनिक अंदाज में कहा कि उन्हें कुछ महीने पहले अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है, अब अपने बच्चे के प्रति मां गंगा का दुलार ही है कि वो आज खुद मुखवा गांव पहुंच पाए हैं। उन्होंने कहा कि वो हर्षिल की धरती पर आकर, अपनी दीदी भुलियों को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें हर्षिल की राजमा और अन्य लोकल प्रोडक्ट भी भेजती रहती हैं।उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले जब वो बाबा केदार के दर्शन के लिए आए थे तो बाबा के दर्शन के बाद उनके मुंह से अचानक ही भाव प्रकट हुआ कि ये दशक उत्तराखंड का होने जा रहा है। ये भाव भले ही उनके थे, लेकिन इसके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति बाबा केदार की थी। अब बाबा के आशीर्वाद से ये शब्द धीरे-धीरे सच्चाई में बदल रहे हैं। ये दशक अब उत्तराखंड का बन रहा है। उत्तराखंड की प्रगति के लिए, नए-नए रास्ते खुल रहे हैं, जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड नित्य नए लक्ष्य और संकल्प लेते हुए, उन्हें पूरा कर रहा है।प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन तीर्थाटन-पर्यटन पर जोर देते हुए कहा कि इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।उन्होंने इस अभिनव पहल के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड के लिए अपने टूरिज्म सेक्टर को बहुआयामी या बारामासी बनाना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में 356 दिन का पर्यटन जरूरी है। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में कोई भी पर्यटन सीजन ऑफ नहीं रहे, बल्कि हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे।उन्होंने कहा कि अभी पहाड़ों पर मार्च से जून के बीच ही ज्यादातर पर्यटक आते हैं, जबकि इसके बाद पर्यटकों की संख्या बहुत कम हो जाती है। अभी सर्दियों के सीजन में होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे खाली पड़े रहते हैं। ये असंतुलन साल के बड़े हिस्से में उत्तराखंड की आर्थिकी को सुस्त कर देता है।

सीएम साय की मां ने सरकारी अस्पताल में कराया स्वास्थ्य परीक्षण, आमजन की तरह सामान्य प्रक्रिया से कराई जांच

रायपुर। जब बेटा सीएम हो तो मां के लिए हर व्यवस्था आसान हो जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की माता जसमनी देवी ने अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल का रुख किया. वे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेकाहारा पहुंची, जहां उन्होंने बिना किसी प्रोटोकॉल के सामान्य जन की तरह स्वास्थ्य परीक्षण कराया.

आमजन की तरह सीएम की मां ने सामान्य प्रक्रिया के तहत जांच कराई, जिससे मुख्यमंत्री की सहजता और सरलता की छवि को और बल मिला. उनके इस कदम से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में जनता के विश्वास को भी प्रोत्साहन मिलेगा. मुख्यमंत्री स्वयं भी आमजन से जुड़ने और सरकारी सुविधाओं को सुलभ बनाने पर जोर देते रहे हैं. उनकी माता का यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश देता है.

महाकुंभ में बब्बर खालसा का आतंकी करना चाहता था हमला: डीजीपी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से गुरूवार तड़के गिरफ्तार किया गया बब्बर खालसा इंटरनेशनल (क्च्यड्ढ) का आतंकी लजर मसीह महाकुंभ के दौरान अशांति फैलाकर भारत से फरार होना चाहता था। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने पत्रकारों को यह जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में बृहस्पतिवार तड़के कौशांबी जिले से बीकेआई के सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह को गिरफ्तार किया गया। डीजीपी कुमार ने कहा कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इस आतंकी की गिरफ्तारी से पाकिस्तान से भारत में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी की पुष्टि भी हुई है।

लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीजीपी कुमार ने कहा कि मसीह ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। उन्होंने कहा, हालांकि, धार्मिक आयोजन में कड़ी सुरक्षा जांच के कारण वह अपनी साजिश को अंजाम नहीं दे सका। उन्होंने कहा कि साजिश को अंजाम नहीं दे सकने के बाद मसीह का इरादा फर्जी पासपोर्ट का उपयोग कर भारत से फरार होने और पुर्तगाल में शरण लेने का था। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसका बब्बर खालसा के एक सदस्य के साथ संबंध था जो पहले ही फर्जी यात्रा दस्तावेज के जरिए दुबई से भागा है।

डीजीपी ने बताया कि मसीह पाकिस्तान में आईएसआई के तीन एजेंटों के संपर्क में था और वह पूर्व में हथियारों और हेरोइन की तस्करी के मामले में जेल जा चुका है, लेकिन 24 सितंबर 2024 को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में इलाज के दौरान भाग गया था।उन्होंने बताया कि भागने के बाद उसने 23 अक्टूबर 2024 को पंजाब के बटाला में स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के इशारे पर गोली चलाई थी जिसके बाद वह सोनीपत और दिल्ली में छिपा रहा।कुमार ने बताया कि मसीह पंजाब में पुलिस चौकियों पर हमलों में शामिल बीकेआई के सदस्यों को कूट संकेतों के जरिए ग्रेनेड की आपूर्ति करता रहा है और वह पीलीभीत में मारे गए आतंकी विरेश सिंह उर्फ रवि के भी संपर्क में था।

उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक, मसीह अमेरिका स्थित एक खालिस्तानी आतंकी से जुड़े अजनाला स्थित एक शख्स और कतर में छिपे एक अन्य आतंकी के निरंतर संपर्क में था। पुलिस ने बताया कि उसने कूटरचित मंचों से संवाद किया और उसके मोबाइल फोन डेटा का एसटीएफ साइबर लैब में विश्लेषण किया जा रहा है।डीजीपी कुमार ने कहा, मसीह आतंकी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने में पंजाब के मादक पदार्थ और फिरौती के अपने गिरोह का उपयोग कर रहा था।

प्रमुख समाचार

यूपी से बिहार तक गंगा में गंदा पानी बह रहा: खरगे

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर नमामि गंगे परियोजना को लेकर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि परियोजना के महत्वपूर्ण लक्ष्य अब तक पूरे नहीं हुए हैं और कुल बजट की आधी रकम भी अभी तक खर्च नहीं हुई है। यूपी से बिहार तक गंगा में गंदा पानी बह रहा है। कांग्रेस नेता खरगे ने आरोप लगाया

कि प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा सफाई की अपनी गारंटी भुला दी है। खरगे ने पोस्ट में लिखा, मोदी जी ने कहा था कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने गंगा सफाई की अपनी गारंटी ही भुला दी है! कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि यह योजना देरी और अक्षम कार्यप्रणाली का शिकार हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद में उपलब्ध कराए आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि 2014 में इस परियोजना की शुरुआत के 11 साल बाद भी निर्धारित 42500 करोड़ के बजट में से सिर्फ 19271 करोड़ ही खर्च हुए हैं, यानी अब भी 55 प्रतिशत धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने नवंबर 2024 के राज्यसभा में दिए गए जवाब का हवाला देकर बताया।

आबकारी मंत्री और उनके समर्थकों के घर पर ईडी का छापा

करूर। तमिलनाडु में धन शोधन मामले में ईडी ने गुरुवार को 10 से ज्यादा स्थानों पर छापे मारे। इस कार्रवाई के तहत राज्य के आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके समर्थकों के घरों पर भी छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर छापेमारी की। इनमें प्रमुख रूप से करूर जिले के रायनूर स्थित कोंगू

मेस के मालिक मणि का घर शामिल है। इसके अलावा, इरोड रोड पर सरकारी ठेकेदार एम शंकर आनंद और शक्ति मेस के मालिक कार्थी के आवासों पर भी छापा मारा। ये सभी लोग मंत्री सेंथिल के समर्थक माने जाते हैं। ईडी की यह छापेमारी धन शोधन के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है, जिसके तहत कई अहम स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारी इस कार्रवाई में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री सेंथिल पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें वित्तीय धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे मामले शामिल हैं। ईडी आरोपों की गहन जांच कर रही है, और इससे संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया जा सकता है, जो कानूनी कार्रवाई में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

बिहार में 40 किमी की रफ्तार से आएगा तूफान

नई दिल्ली। नॉर्थ-ईस्ट असम और उसके आस-पास एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके कारण मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके अलावा, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 9 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में प्रभाव डालने की संभावना है। बिहार में बारिश के साथ आंधी, बिजली गरजने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज

हवाएं चलने की संभावना है। 7 और 8 मार्च को गंगा से सटे पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र में उत्तर-पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलीं। इसके कारण इन राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। असम में भी हल्की बारिश हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दिन और रात के तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट आई, जबकि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में 3-4 डिग्री की गिरावट आई।

बांग्लादेश में यूनुस के गलत फैसलों को भुगत रहे लोग

ढाका। बांग्लादेश भी अब कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में आर्थिक संकट बढ़ता ही जा रहा है। यूनुस की गलत नीतियों के कारण देश की जनता त्रस्त है। यूनुस को कुछ समझ नहीं आ रहा कि बांग्लादेश को आर्थिक संकट से कैसे उबारा जाए। बांग्लादेश की जनता को खाने के लाले पढ़ रहे हैं। यूनुस अपने ही

फैसलों में फंस गए हैं। विदेशी निवेशक अब बांग्लादेश में निवेश करने से कतरा रहे हैं। खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है। मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश संभला नहीं जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों का कहना है कि स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश को पैसा देना बंद कर दिया है। पिछले छह महीनों में विदेशी निवेश में 71 फीसदी की भारी गिरावट आई है। खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर 10.72 फीसदी पर पहुंच गई है, जबकि बाकी चीजों की महंगाई दर 9.32 फीसदी है। बांग्लादेश सरकार ने नोट छापना बंद कर दिया है। इसके कारण बाजार में नकदी का संकट पैदा हो गया है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं। रोजगार नहीं हैं।

मुहम्मद शमी ने नहीं रखा रोजा तो हो गया विवाद

बरेली। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उन पर रमजान के महीने में रोजा न रखने का आरोप लगाते हुए, इसे शरीयत की नजर में गुनाह करार दिया है।दरअसल, दुबई में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के

सेमीफाइनल मैच के दौरान मोहम्मद शमी की एनर्जी ड्रिंक पीते हुए एक तस्वीर वायरल हुई थी। इस पर मौलाना रजवी ने नाराजगी जताई और कहा कि शमी ने रोजा नहीं रखकर इस्लामिक नियमों का उल्लंघन किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, इस्लाम में रोजा एक फर्ज है, और जो इसे जानबूझकर नहीं रखता, वह गुनहगार होता है। शमी को रोजा रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे वह शरीयत की नजर में गुनहगार बन गए हैं। मैं उन्हें नसीहत देता हूं कि वह इस्लामिक नियमों का पालन करें और अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों को निभाएं।मौलाना रजवी के इस बयान के बाद बीजेपी खुलकर शमी के समर्थन में आ गई है।

–

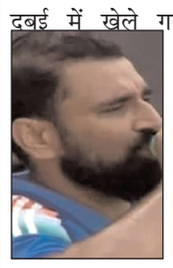

व्यापार युद्ध भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा

सच्चिदानंद शेकटकर

दूसरी बार बने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव के दौरान लिए गए वादों को निभाने में बड़ी सक्रियता के साथ जुट गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने निर्यात शुल्क बढ़ाकर ट्रेड वार यानी व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर छेड़ने का एक तरफा फैसला किया है अब उनको जवाब मिलना भी शुरू हो गया है। सबसे बड़े वैश्विक ट्रेड वार की शुरुआत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडा, मेक्सिको और चीन से आयात होने वाले कई उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। अमेरिका ने जहां कनाडा और मेक्सिको से स्टील अल्युमिनियम समेत कई धातुओं और अन्य उत्पादों के आयात पर 25 प्रतिशत टैक्स लगा दिया है जबकि कनाडा के ई ऊर्जा उत्पादन के आयात पर अमेरिका ने 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। अमेरिका ने चीन से होने वाले हर आयात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगा बढ़ा दिया है पहले यह शुक्ल 10 प्रतिशत था। अमेरिका ने शुल्क लगाने का जो बड़ा फैसला किया है वहीं चीन और कनाडा ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा दिया है। चीन ने भी अमेरिका से आयात कई कृषि उत्पादों जैसे चिकन, सोया, मक्का और बीफ पर 15 प्रतिशत शुल्क लगाने का जवाबी ऐलान कर दिया है। वर्ष 2023 में चीन ने अमेरिका से 33 अरब डॉलर के कृषि उत्पादक आयात किए थे जिस पर अब असर पड़ेगा और इससे चीन को नुकसान भी होगा। वहीं दुनिया के दो बड़े देश अमेरिका और चीन समेत चार प्रमुख देशों के बीच जो व्यापार युद्ध छिड़ा है उसके असर का भी आकलन किया जा रहा है। आकलन इस बात का भी किया जा रहा है कि इस व्यापार युद्ध से भारत को कितना फायदा होने जा रहा है। यह उम्मीद की जा रही है

कि इस व्यापार युद्ध से भारत से अमेरिका को निर्यात में 10 प्रतिशत तक बढोतरी हो सकती है। भारत से कुल 8.40 लाख करोड रुपए का निर्यात अमेरिका को हो सकता है अभी भारत अमेरिका को 7.63 करोड रुपए के समान का निर्यात और 3.65 लाख करोड रुपए का आयात करता है। यह व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है।भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में शिपमेंट बढ़ाने में मदद मिलेगी। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2019 में चीन पर अधिक टैरिफ ड्यूटी लगाई थी तभी भारत चौथा सबसे बड़ा लाभ पाने वाला देश बन गया था। विशेषज्ञों का यह मानना है कि व्यापार युद्ध से भारत को फायदा उठाने के लिए तुरंत होमवर्क करना चाहिए भारत को तीन मोर्चे पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। यह तीन मोर्चे हैं प्रोडक्शन ग्रोथ और डिमांड। प्रोडक्शन बढ़ाने से रोजगार में फायदा मिलेगा लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा तो बाजार में डिमांड बढने वाली है इससे इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी यह तीनों फैक्टर भारत के पक्ष में जा सकते हैं। लेकिन विदेशी निवेशकों को रोकना भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। वही अमेरिका द्वारा छेड़े गए ट्रेड वॉर को लेकर इस वार से जुड़े रहे चीन का यह कहना है कि अमेरिका युद्ध चाहता है तो हम अंत तक लडने के लिए तैयार हैं फिर चाहे वह टैरिफ बार हो या ट्रेड वॉर हो या और कोई युद्ध हो। वही ट्रेड वॉर से प्रभावित कनाडा के प्रधानमंत्री का यह कहना है कि ट्रंप खुद को चतुर समझते हैं लेकिन टैरिफ लगाकर मूर्खता कर रहे हैं। यह भी विशेषज्ञ बताते हैं कि अमेरिका को घेरने के लिए ब्रिक्स जैसे मजबूत संगठन के देश आपस में नॉर्मल टैरिफ का नियम लागू कर सकते हैं जिससे अमेरिका अलग-थलग पड़ सकता है। अभी तो व्यापार युद्ध की शुरुआत हुई है इसके नतीजों का आकलन करने में अभी कुछ वक्त तो लगेगा।

नक्सलियों ने 2 गांव के 8 परिवारों को दी मारने की धमकी

■ पीड़ितों ने थाने में की शिकायत

जगदलपुर। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सरहदी सीमा में बसे 2 गांव के 8 परिवारों को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी है। नक्सलियों ने इन लोगों को गांव से बेदखल कर दिया। जिसके बाद पीड़ित परिवारों ने मामले की शिकायत दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दंतेवाड़ा और बीजापुर सीमा से लगे बारसूर थाना क्षेत्र के तुषवाल पंचायत के दो गांव के आठ परिवारों को नक्सलियों ने जान से मारने का धमकी दी और गांव से बेदखल कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि तीन दिन पहले तुषवाल पंचायत के तोड़मा और कोहकाबेड़ा गांव के आठ परिवार को नक्सलियों ने गांव छोड़ने का फरमान जारी किया। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के शरहद में बसे तुषवाल पंचायत के सभी पीड़ित परिवार बताए जा रहे हैं। नक्सलियों के इस फरमान के बाद से इन सभी परिवार के लोगों में दहशत देखी जा रही है। पीड़ित परिवार गांव छोड़कर निकल पड़े है और अब बस्तर जिले के किलेपाल, वाहनपुर गांव में पनाह लेने पहुंच रहे हैं।

नक्सलियों ने इन पीड़ित परिवारों के ऊपर पुलिस मुखबिर करने और थुलथुली मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए तीन दिन पहले गांव में बैठक की थी। जहां नक्सलियों के पूर्वी बस्तर डिविजन के करीब 50 की संख्या में नक्सली गांव मे पहुंचे और इन परिवारों को धमकाते हुए गांव से बेदखल करने की बात कही। इन पीड़ितों ने बारसूर थाना में जाकर मामला दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

दंतेवाड़ा में 2 महिला नक्सलियों का सरेंडर

दंतेवाड़ा। 2 हार्डकोर महिला माओवादियों ने गुरुवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाली दोनों महिला नक्सली सरकार की लोन वर्राटू योजना से प्रभावित हैं। पूरे बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के लिए एंटी नक्सल ऑपरेशन और लोन वर्राटू, पूर्ना नारकोम योजना चलाई जा रही है। सरकार की सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। जिला प्रशासन नक्सलियों के पुनर्वास के लिए लगातार प्रचार प्रसार भी कर रही है।

महिला नक्सलियों का सरेंडर- सरेंडर करने वाली दोनों महिला नक्सली लंबे वक्त से माओवादी संगठन से जुड़ी रही हैं। दोनों महिला नक्सली मलांगेर एरिया कमेटी में सक्रिय रही हैं। सरेंडर करने के बाद दोनों ने कहा कि वो अब हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा से जुड़कर काम करेंगी।

कुमारी भीमे वेट्टी नक्सलियों के प्लाटून नंबर 20 की सदस्य थी। 23 साल की कुमारी भीमे वेट्टी ओडिशा के मलकानगिरी के गूगेपदर थाने के मातली की रहने वाली है। जोगी कुंजाम मलांगेर/पालनार एलओएस सदस्य थी। 30 साल की जोगी कुंजाम किरंदुल के हिरोली की रहने वाली है। दोनों महिला नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक गौरव राय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन के सामने डीआरजी दफ्तर दंतेवाड़ा में सरेंडर किया।

पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 25 हजार की सहायता राशि के साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलने वाली सुविधाएं जैसे 3 वर्ष तक नि:शुल्क आवास तथा भोजन, स्किल डेवलपमेंट हेतु प्रशिक्षण, कृषि भूमि की सुविधा दी जाएगी। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 217 इनामी सहित कुल 904 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला लिया है।

टाऊन क्लब ग्राउंड में गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ

सांसद महेश कश्यप ने किया उद्घाटन

जगदलपुर। दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्थित टाऊन क्लब ग्राउंड में गांधी शिल्प बाजार, हस्तशिल्प प्रदर्शनी एवं बिक्री मेला का आयोजन किया गया है। यहां देश के कोने-कोने से आए हस्तशिल्प कलाकारों द्वारा निर्मित अनूठे एवं उत्कृष्ट उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका आज बस्तर सांसद महेश कश्यप ने फीता काट कर शुभारंभ किया।

उद्घाटन समारोह में बस्तर सांसद महेश कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति और सम्मानित अतिथि भी शामिल हुए। अपने उद्घाटन भाषण में सांसद महेश कश्यप ने कहा कि गांधी शिल्प बाजार जैसी प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। मुख्य अतिथि ने उपस्थित लोगों से कारीगरों से जुड़ने और उनके काम का समर्थन करने का भी आग्रह किया।

गांधी शिल्प बाजार कारीगरों के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने और व्यापक दर्शकों से जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। प्रदर्शनी में भारत के कई राज्यों के कारीगरों और बुनकरों के 20 शिल्प रूप शामिल हैं, जिनमें हाथ से बुने हुए वस्त्र, बेंत और बांस के शिल्प, मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी और बहुत कुछ दिखाया गया है।

गांधी शिल्प बाजार का यह आयोजन 10 मार्च तक रोजाना सुबह 10 से रात 9 बजे तक होगा। गांधी शिल्प बाजार में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। यहां लोगों को एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट व शिल्प सामग्री मिलेगी। गांधी शिल्प बाजार का विशेष आकर्षण कोसा साड़ी, ब्लॉक प्रिंट, लेदर क्राफ्ट, ढोकरा शिल्प, ज्वेलरी, बस्तर शिल्प, बांस शिल्प, एम्ब्रायडरी वर्क, चंदेरी साड़ी, टेराकोटा, ओडिशा पट्टचित्र, कालीन सिल्क, बनारसी साड़ी, जूट क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट आदी है।

पांचवीं बार भाजपा प्रत्याशी को मिली बालोद जनपद की कमान

बालोद। जनपद पंचायत बालोद में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को शिकस्त दी। इसके बाद से पूरा माहौल भगवामय हो गया। लागतार यह पांचवी बार होगा, जब भाजपा की सरकार यहां जनपद में काबिज है और इस किले को भेद पाने में कांग्रेस असमर्थ साबित हुई। भाजपा प्रत्याशी सरस्वती टेमरिया को 16 जनपद सदस्यों में से 10 ने अपना समर्थन दिया। वहीं, छह जनपद सदस्यों का समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी अमृता नेताम के पक्ष में रहा इस जीत के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला।

सामान्य घर की बेटी को बनाया प्रत्याशी

भाजपा नेता राकेश यादव ने कहा कि जीत का हमारा सिलसिला बरकरार है और यह भाजपा का वो किला है, जिसे कांग्रेस 25 सालों से भेद नहीं पाई है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और सीएम विष्णुदेव साय के सुशासन को जाता है। प्रत्येक उन कार्यकर्ताओं को जो निरंतर मेहनत करते रहे। हमने एक सामान्य परिवार की बेटी को टिकट दिया वो जीतकर भी आए अब वो जनता के सपनों पर खरा उतरने के लिए तैयार हैं।

आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से जनपद पंचायत बालोद में कार्यकर्ताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। वहीं, नामांकन सहित जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी। जिले के दिग्गज नेता भी पहुंचने लगे थे, लेकिन जनपद पंचायत के इस चुनाव में भाजपा ने पांचवीं बार अपना परचम लहराया है।

सेवा ही कर्तव्य

जनपद अध्यक्ष बनकर आई सरस्वती टेमरीया ने कहा कि जनपद का ये चुनाव मेरे लिए बेहद अहम रहा। पार्टी ने मुझे इस काबिलसमझा कि मुझे टिकट दिया और जो भी उम्मीदें पार्टी को मुझसे हैं और मेरे क्षेत्र की जनता को मुझसे उम्मीदें हैं उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगी। इस जीत का श्रेय मैं हर उस कार्यकर्ताओं को देना चाहती हूं, जो निरंतर मेहनत करते रहे।

एसईसीएल ने लांच किया जटायु डैशबोर्ड

कर्मियों को कामकाज से जुड़े विभिन्न नियम एवं दिशानिर्देश एक ही जगह उपलब्ध हो सकेंगे

बिलासपुर। एसईसीएल मुख्यालय में 5 मार्च बुधवार को आयोजित महाप्रबन्धक समन्वय बैठक में सीएमडी श्री जेपी द्विवेदी द्वारा एसईसीएल जटायु डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। सतर्कता एवं सिस्टम विभाग के संयुक्त प्रयास से विकसित इस ऑनलाइन डैशबोर्ड में कोल इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न नियम, सर्कुलर, एसओपी, आदि का संकलन किया गया है। इस पहल से एसईसीएल कर्मियों को कामकाज से जुड़े विभिन्न नियम एवं दिशानिर्देश एक ही जगह उपलब्ध हो सकेंगे तथा नॉलेज अपडेट के माध्यम से निवारक सतर्कता को बढ़ावा मिलेगा।

इस दौरान निदेशक तकनीकी (संचा. सह यो/परि) श्री एन फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (कार्मिक) श्री बिरंची दास एवं निदेशक (वित्त) श्री डी सुनील कुमार, सीवीओ श्री हिमांशु जैन (वीसी के माध्यम से) संचालन क्षेत्रों के महाप्रबन्धक एवं मुख्यालय के विभागाध्यक्षगण उपस्थित रहे।

महान महाकाव्य रामायण में, जटायु सतर्कता, कर्तव्य और धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक थे। न्याय और सुरक्षा के प्रति उनके समर्पण से प्रेरित होकर, एसईसीएल सतर्कता और प्रणाली विभाग ने जटायु डैशबोर्ड विकसित किया है- जो कार्य-संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करके की दिशा में कार्य करेगा।

यह पहल सुनिश्चित करती है कि अधिकारियों को कोल इंडस्ट्री से संबन्धित दैनिक कार्यों से जुड़े नियमों, दिशानिर्देशों और मानदंडों की जानकारी हो, जिससे कार्य संचालन में शंका ना रहे और निर्णय लेने में आसानी हो। डैशबोर्ड सार्वजनिक उद्यम विभाग, व्यय विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कोल इंडिया और एसईसीएल जैसी प्रमुख संस्थाओं द्वारा जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों और एसओपी को समेकित करता है। सुलभ सर्चिंग के लिए उचित टैगिंग के साथ, जारी करने वाली एजेंसी, क्षेत्र, विषय, वर्ष और तिथि के अनुसार दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया गया है।

टीम द्वारा एआई -संचालित चैटबॉट को एकीकृत करके जटायु डैशबोर्ड को और बेहतर बनाने की कल्पना की गई है जो अधिकारियों के प्रश्नों के लिए विश्वसनीय, त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करेगा।

जटायु डैशबोर्ड में एक योगदान अनुभाग भी है, जो अधिकारियों को प्रासंगिक पीडीएफ अपलोड करके अनुपलब्ध संसाधनों को शामिल करने का सुझाव देने की अनुमति देता है। इन सबमिशन की समीक्षा एडमिन द्वारा की जाएगी और उन्हें रिपॉजिटरी में शामिल किया जाएगा। आने वाले दिनों में, एआई चैटबॉट को टेंडरिंग, अनुबंध प्रबंधन, भूमि और पुनर्वास, वित्त, मानव संसाधन, और प्रमुख परिचालन क्षेत्रों से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा।

तत्कालीन निगम आयुक्त के निलंबन उपरांत प्रवीण वर्मा नगर निगम के आयुक्त बने

जगदलपुर। नगर निगम जगदलपुर के आयुक्त निर्भय साहू को भारत माला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कर भूमि मालिकों को ज्यादा मुआवजा राशि का भुगतान करने का आरोप में छत्तीसगढ़ के अवर सचिव क्लेमेन्टीना लकड़ा के द्वारा निलंबित करने के बाद उनकी जगह अब बस्तर जिले के अपर कलेक्टर प्रवीण कुमार वर्मा को नगर निगम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बस्तर कलेक्टर हरिस एस. द्वारा जारी आदेश में प्रवीण वर्मा अगले आदेश तक निगम आयुक्त का प्रभार संभालेंगे।

उल्लेखनिय है कि निर्भय साहू के एसडीएम रहते रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए उस इलाके में भूमि अधिग्रहण का काम किया गया था। तब शिकायत मिली थी कि इन्होंने जिनकी निजी भूमि प्रोजेक्ट के लिए ली थी, उन्हें मुआवजा राशि से अधिक का भुगतान कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई थी। जिसके बाद जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था, समिति ने जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी थी। जिसके बाद अधिकारियों ने जांच में सही पाया। फिर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निर्भय साहू पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। विदित हो कि कुछ महीने पहले ही वे जगदलपुर नगर निगम के आयुक्त बने थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भाटापारा में जल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा

भाटापारा। भाटापारा नगर पालिका अध्यक्ष अस्विनी शर्मा एवं उपाध्यक्ष दिलीप छाबड़िया ने नगर पालिका सीएमओ के साथ जल विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में शहर में जल आपूर्ति व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक के बाद नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। उन्होंने जल आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट को दूर करने के लिए आवश्यक सुधार कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने नागरिकों को स्वच्छ और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया। नगर पालिका अध्यक्ष अस्विनी शर्मा ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं में अपेक्षित सुधार के लिए प्रशासन तत्पर है और जनहित में सभी आवश्यक सुधार कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। इस बैठक में जल आपूर्ति व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों को लेकर नगरवासियों में सकारात्मक उम्मीदें जताई जा रही हैं।

नारायणपुर में राशन से लदा ट्रैक्टर पलटा

जगदलपुर। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में बुधवार को ग्रामीणों से भरा ट्रैक्टर पीडीएस का चावल लेकर गांव जा रहा थी कि अचानक से ट्रैक्टर पलट जाने से उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी देते हुए छोटे डोंगर थाना प्रभारी ने बताया कि 5 मार्च के करीब 8 से 10 बजे रात्रि में ग्राम मडोनार के आगे नाला के पास एक ट्रैक्टर पलट गया। जिसमें 16 ग्रामीण बैठे हुए थे, इनमे बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ग्राम ओरछा से पीडीएस का चावल (राशन) लेकर ग्राम तोयामेटा, कावानार, मुसनार के ग्रामीण बैठे कर घर जा रहे थे कि अचानक से नाला के पास ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 2 पुरुष और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। 5 महिला, 6 पुरुष और एक बच्ची घायल हो गई। 12 घायलों को छोटेडोंगर प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र लाया गया, घायलों का इलाज जारी है। 2 गंभीर रूप से घायलों को छोटेडोंगर पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद रिफर कर नारायणपुर भेजा गया है।

खेत में पानी लगाने जा रहे किसान पर बाघ का हमला

बिलासपुर। बिलासपुर खेत में पानी लगाने जा रहे किसान के ऊपर बाघ ने गुरुवार सुबह-सुबह हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के ग्रामीणों की मदद से घायल को तखतपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन घायल की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे सिम्स रेफर किया गया है। बाघ के हमले से क्षेत्र में दहशत की स्थिती बनी हुई है। जानकारी के अनुसार ग्राम कठमुण्डा निवासी किसान शिवकुमार जायसवाल (47) पिता जनक जायसवाल गांव के राजू के कठमुण्डा के तुरतुरिया खार में खेती-बाड़ी का काम करता है। वहीं आज सुबह करीब 6 बजे खेत में पानी लगाने के लिए खेत की ओर जा रहा था। तभी पुलिया के पीछे छिपे बाघ की दहाड़ने की आवाज आई और पलट कर देखा तो बाघ ने अचानक से उसपर हमला कर दिया। जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर, हाथ और सिर मे गंभीर चोंट आई है। ग्रामीणों की मदद से उसे तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर रेफर कर दिया गया।

बरातियों से भरी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी

कबीरधाम। कबीरधाम जिले में बरात से वापस हो रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार चल रहा है। यह हादसा कवर्धा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कवर्धा-जबलपुर नेशनल हाईवे मार्ग स्थित ग्राम हरिनछपरा के पास हुआ है। जानकारी अनुसार, पांडातराई थाना क्षेत्र के ग्राम छाटा (मड़मड़ा) से बरात ग्राम दनियाखुर्द (सहसपुर लोहारा) गई थी। रात में कार्यक्रम के बाद स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक सीजी-11-एएक्स-7920 में बैठकर करीब 10 लोग वापस हो रहे थे, तभी स्कॉर्पियो पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास से गुजरने वाले लोगों ने डॉयल 112 व 108 एंबुलेंस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने घायलों को जिला अस्पताल कवर्धा में भर्ती कराया। इस हादसे में जख्मू चंद्रवंशी (40) पुत्र बंसी चंद्रवंशी मौत हो गई है। वहीं, अन्य तीन गंभीर का उपचार जारी है। गुरुवार को मृतक के शव का पीएम बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

ठग को बैंक खाता किराए में देने वाले 28 पर मामला दर्ज

बेमेतरा। बेमेतरा पुलिस टीम ने साइबर ठगी के लिए किराए पर खाता देने वाले 28 खाताधारक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि इनके खातों से साइबर ठगी की 5 लाख 4 हजार रुपये से अधिक राशि का ट्रांजेक्शन हुआ है। साइबर टीम को जांच के दौरान खातों से ठगी की रकम के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली। इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रही साइबर ठगी की राशि का ट्रांजेक्शन होना पाया गया। सिटी कोतवाली बेमेतरा प्रभारी राकेश साहू ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत संचालित बैंकों के अकांउट की जांच में पाया गया कि कुल 28 बैंक खाताधारकों के खाते में साइबर धोखाधड़ी की राशि मिली है। अलग-अलग खातों में करीब 5 लाख 4 हजार रुपये से अधिक राशि का ट्रांजेक्शन हुआ है। ऐसे 28 खाताधारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए बेमेतरा पुलिस ने लोगों से अपील कर कहा कि बैंक खाता खोलते समय पूरी सतर्कता बरतें।

कलेक्टर और एसपी के हाथों से लगे पौधों की नहीं हुई देखभाल

■ धमतरी में सूख गए वीआईपी पौधे

धमतरी। पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने के नाम पर धमतरी में पौधा रोपण किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन के कंपोजिट भवन में मौजूद उद्यानिकी विभाग के ठीक बगल में फेंसिंग कर के अलग अलग प्रजाति के फलदार, छायादार पेड़ों के पौधे रोपे गए।

ये पौधे आम नहीं बल्कि वीआईपी पौधे थे। किसी को कलेक्टर ने रोपा, किसी को एसपी ने, कोई पौधा जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम तो कोई और किसी खासमखास के नाम। आज ये पौधे सूख चुके हैं या मर चुके हैं या मरने वाले हैं।

कुछ माह पहले ही कम्पोजिट भवन परिसर में जनप्रतिनिधियों, ग्रीन आर्मी की महिलाओं, अधिकारी, कर्मचारियों ने पौधरोपण किया था। खाद और पानी नहीं मिलने से एक भी पौधा सुरक्षित नहीं है। लोगों का कहना है कि इन पौधों में खाद तो छोड़िए समय पर पानी तक नहीं डाला गया, जबकि इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी उद्यानिकी विभाग की थी, जो ठीक बगल में मौजूद है। कंपोजिट बिल्डिंग के पाइपों से लगातार पानी बह रहा है, लेकिन कुछ ही मीटर दूर इन पौधों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

एक नारा लिखा हुआ पोस्टर उस पौधे पर है, जिसमें प्रशासन के अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने नाम से पौधे रोपे थे। नारी शक्ति से जल शक्ति लेकिन जल की शक्ति नहीं दी गई, इसलिए पौधे मर गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक पुरानी कहावत है, चिराग तले अंधेरा। इस कहावत की मिसाल धमतरी में देखने को मिली है। उद्यानिकी विभाग के बगल में रोपे गए वीआईपी पौधे पानी की कमी से सूखने और मरने लगे हैं।

वहीं उद्यानिकी विभाग का कहना है कि उनके पास सींचने के लिए पानी और साधन नहीं है। फिर भी दावा है कि पूरी कोशिश पौधों को बचाने के लिए की जा रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर स्नेहलता सिन्हा ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम पर के तहत बरसता में वृक्षारोपण किया गया था। यहां पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जिसकी वजह से पौधों को बचाने में दिक्कत आ रही है।

नए पौधे लगाए जाएंगे- असिस्टेंट डायरेक्टर ने यह भी कहा कि हम अपनी तरफ से पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं। बीच बीच में जो पौधे खत्म हो गए हैं, उनकी जगह नया पौधारोपण कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक पौधे हम बचा सकें।

संरक्षा के सजग प्रहरियों को महाप्रबंधक ने सम्मानित किया

बिलासपुर। रेल परिचालन में संरक्षा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सजगता एवं बेहतर संरक्षा कार्य में सहभागिता निभाने वाले रेल संरक्षा के सजग प्रहरी कर्मचारियों का सम्मान महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा हर माह आयोजित संरक्षा बैठक के दौरान किया जाता है । इसी कड़ी में 5 मार्च' को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत संरक्षा कोटि के 3 कर्मचारियो को उनके उत्कृष्ट एवं सराहनीय संरक्षा सबंधी कार्य निष्पादन के लिए महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश के द्वारा सम्मानित किया गया।

श्री गणेश राम, पॉइंट्स मैन- ए/ सरोना / रायपुर मंडल ने 5 फरवरी को अपने ड्यूटी के दौरान चलती ट्रेन के मार्ग में हॉट एक्सल पता कर सर्व संबन्धित को सूचित किया और फिर आगे की कार्यवाही कर ट्रेन को संरक्षित रवाना किया गया ।

श्री मनोज कुमार, टीएम-IV (गेट कीपर) /डोंगरगढ़ / नागपुर मंडल ने 2 फरवरी को रेलवे फाटक क्रमांक 477 पर डोंगरगढ़-पनियाजोब के बीच ड्यूटी के दौरान उन्हे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी । इन्होने तुरंत ही रेलवे फाटक के आस-पास निरीक्षण किया और पाया कि अप लाइन पर ओएचई तार टूटा हुआ है । उन्होंने तत्काल सर्व संबन्धित को सूचित किया और रेल लाइन को बैनर फ्लैग लगाकर संरक्षित किया। तत्पश्चात, आगे की कार्यवाही कर इस लाइन पर ट्रेनों को रवाना किया गया ।

श्री. कृष्णकांत तिवारी, ट्रैक मेंटेनर-IV / आमगांव / नागपुर मंडल 1 फरवरी को, ठंडे मौसम में अपने गश्त ड्यूटी के दौरान रात में लगभग 01.25 बजे, डाउन लाइन पर रेल फ्रैक्चर देखा । उन्होंने तुरंत बैनर फ्लैग द्वारा ट्रैक की सुरक्षा की और फिर आगे की कार्यवाही कर ट्रैक को सामान्य यातायात के लिय ठीक किया गया। संरक्षा कोटि के कर्मचारी को सम्मानित किए जाने के अवसर पर अपर महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी अन्य विभागाध्यक्ष सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत किए जाने का आदेश जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत किए जाने की अपनी घोषणा को पूरा करके राज्य के लाखों शासकीय सेवकों को होली पर्व से पूर्व सौगात दी है। यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में शासकीय सेवकों को 53 प्रतिशत डीए किए जाने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा के परिपालन में शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने का आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके 53 प्रतिशत किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अब उन्हें 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अब उन्हें 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। यह वृद्धि 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगी और इसका भुगतान मार्च 2025 के वेतन के साथ अप्रैल माह में किया जाएगा।

आरंग में निर्विरोध निर्वाचित हुए भाजपा के अध्यक्ष - उपाध्यक्ष

रायपुर। आरंग में संपन्न जनपद अध्यक्ष व

उपाध्यक्ष के चुनाव में प्रभारी रहे वरिष्ठ भाजपा नेता अंजय शुक्ला की महती भूमिका रही। उन्होने सभी सदस्यों के बीच सहमति बनाते हुए निर्विरोध निर्वाचन करवाया। भाजपा के टिकेश्वरी साहू अध्यक्ष व रिंकु चंद्राकर उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री शुक्ला ने बताया कि आरंग विधायक श्री खुशवंत गुरु,जिलाध्यक्ष श्याम नारंग व नपा अध्यक्ष संदीप जैन का विशेष सहयोग व मार्गदर्शन मिला।

चुनाव सामग्री वितरण से अनुपस्थित छह कर्मचारियों पर प्रशासन की कार्रवाई

रायपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के तीसरे चरण के तहत कटघोरा में चुनाव सामग्री वितरण कार्य के दौरान बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले छह कर्मचारियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिला पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश नाग द्वारा इन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों में विकासखंड कोरबा के प्राथमिक शाला उपरपारा चचिया के सहायक शिक्षक विरेन्द्र कुमार खैरवार, प्राथमिक शाला गोकुल नगर के सहायक शिक्षक विमल पाटले, प्राथमिक शाला धौराभांठा के सहायक शिक्षक महेंद्र कुमार राठौर, प्राथमिक शाला बेंगचूलभांठा के सहायक शिक्षक हितेन्द्र कुमार रात्रे, विकासखंड कटघोरा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छुरी के सहायक ग्रेड-03 अभिषेक सिंह राठौर तथा विकासखंड पाली के सेजेस तिवरता के व्याख्याता रामकुमार चन्द्रा शामिल हैं।

नवपदस्थ आयुक्त विश्वदीप ने रायपुर नगर निगम में सम्हाला पदभार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन

विभाग द्वारा नवपदस्थ रायपुर नगर निगम आयुक्त एवं रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री विश्वदीप ने गुरुवार को अपरान्ह नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गॉधी सदन के द्वितीय तल पर निगम आयुक्त कार्यालयीन कक्ष में निगम आयुक्त एवं रायपुर स्मार्ट सिटी के प्रबंध संचालक का प्रशासनिक पदभार सम्हाल लिया है। जिला धमतरी के नवपदस्थ कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने नवपदस्थ आयुक्त श्री विष्वदीप को नगर निगम आयुक्त और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक का प्रशासनिक पदभार सौपा। इस अवसर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा बैच 2018 के नवपदस्थ जिला धमतरी कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा बैच 2019 के नवपदस्थ रायपुर नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप को रायपुर नगर निगम अपर आयुक्त सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, यू.एस. अग्रवाल, पंकज के. शर्मा, विनोद पाण्डेय, श्रीमती कृष्णा खटीक, मुख्य अभियंता श्री यू.के. धलेन्द्र, उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा, श्री जसदेव सिंह बाबरा, श्रीमती प्रीति सिंह, डॉ. दिव्या चंद्रवंशी, जोन 4 जोन कमिश्नर श्री अरूण ध्रुव, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के महाप्रबंधक तकनीकी श्री पंकज कुमार पंचायती सहित रायपुर नगर निगम एवं रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बुके प्रदत्त कर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान निवर्तमान नगर निगम आयुक्त एवं नवपदस्थ जिला धमतरी कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के परिवारजनों की नगर निगम आयुक्त कक्ष में उपस्थिति रही।

किसानों को नहीं मिला 2023-24 का गन्ना का पेमेंट

बंद होने के कगार पर शक्कर कारखाना, भाजपा विधायक के सवाल पर स्पीकर ने समय पर पेमेंट के साथ दिए जांच के निर्देश

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन पंडरिया विधानसभा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने की माली हालत पर विधायक भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण में सवाल उठाया। विधायक ने बताया कि किसानों को 2023-24 का गन्ने का पेमेंट नहीं मिला है। न समर्थन मूल्य का भुगतान हो रही, और न ही बोनस का। इस पर स्पीकर डॉ। रमन सिंह ने समयबद्ध पेमेंट के साथ सारे बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए।

भाजपा विधायक भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण में सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में शक्कर कारखाने की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। 8 हजार किसान गन्ना बेचते हैं। हर किसान के परिवार मे 5-6 लोग हैं। किसानों को अब तक 2023-24 का गन्ना का पेमेंट नहीं मिला है। न समर्थन मूल्य का भुगतान हो रहा और न ही बोनस का।

विधायक ने बताया कि शुगर फैक्टरी पर 81 करोड़ का लोन था, जिसके एवज में ब्याज समेत 121 करोड़ पटाया जा चुका है। उन्होंने मांग की कि ब्याज की दर को घटाया जाए, साथ ही गन्ना पेराई की दर 350 रुपए दी जा रही है, जबकि प्राइवेट कंपनी 450 रुपए दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि शक्कर कारखाना को सहकारिता विभाग से कम दर पर अतिरिक्त ऋृण दिया जाए, ताकि उसका आर्थिक संकट दूर हो सके।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार इस पर गंभीर है। आर्थिक संकट दूर करने विशेषज्ञों का सलाह लेकर कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने कहा कि कुप्रबंधन का भार किसानों पर पड़ रहा है। बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, नेता वहां जाकर अपने लोगों को काम देने का दबाव डालते हैं। एक हाईपावर कमेटी भेजकर उसकी समीक्षा कर शक्कर कारखाने के बेहतरी के लिए काम करें।

मंत्री ने कहा कि जल्द ही किसानों की भुगतान की व्यवस्था करेंगे, साथ ही कमेटी बनाकर व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। विधायक अजय चंद्राकर ने समय अवधि निर्धारण करने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, हाई पावर कमेटी भेजकर तत्काल व्यवस्था कीजिए। मंत्री ने कहा, जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि अध्यक्ष महोदय आपके क्षेत्र में आपके सपनों को साकार करने बना है। एशिया के सबसे बेस्ट कारखाने में से एक है। सहकारिता एक बेहतर दुनिया की निर्माण कर सकती है। इस कारखाने को कुप्रबंधन से बचाते हुए इसे नहीं बेचने का आश्वासन दीजिए। मंत्री ने कहा कि 2006 में यह कारखाना बना था। कुछ कुप्रबंधन की वजह से यह स्थिति बनी है। इसे बेहतर करने का काम करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ। रमन सिंह ने समयबद्ध पेमेंट कराने का निर्देश देते हुए कहा कि साथ ही सारे बिंदु पर जांच हो जाए।

गौण खनिज से प्राप्त राशि में अनियमितता पर हुई जांच पर उठा सवाल

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आठवें सत्र के दौरान विधायक राघवेंद्र कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान गौण खनिज से प्राप्त राशि में अनियमितता को लेकर हुई जांच पर सवाल किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि जांच में नियमों का उल्लंघन साबित होने पर छह अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विधायक राघवेंद्र कुमार ने सवाल किया कि जितनी कार्य निविदा आमंत्रित हुई, क्या भावपत्र में किसी तरीके से कोई अनुमति या अनुमोदन किया गया है? अगर जांच कराई गई है तो रिपोर्ट में क्या आया है? उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 2 करोड़ 13 लाख 44 हजार रुपए प्राप्त हुए थे। भाव पत्र के माध्यम से 26 में से 21 कार्य जल प्रदाय से संबंधित हैं, इसमें जांच में पाया कि भंडार नियम का उल्लंघन हुआ है। मामले में 6 अधिकारियों का निलंबन हुआ है। मुख्य अभियंता के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम बनाई है, जिसकी जांच रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। विधायक ने इस पर सवाल किया कि क्या यह सही है एक ही फार्म को 75 लाख का भुगतान किया गया है इन सब पर कानूनी कार्यवाही क्या करेंगे? इस पर उपमुख्यमंत्री ने बताया कि एक ही फार्म नहीं है, और भी फॉर्म है। कमेटी भी बनाई गया है, वह जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। इस पर फिर विधायक ने सवाल किया कि क्या फर्मों को ब्लैक लिस्ट करेंगे? इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके खिलाफ भी रिपोर्ट आएगी, उन पर कार्यवाही की जाएगी।

दिवंगत सदस्यों के निधन की सूचना में देरी पर सदन में उठा सवाल

छत्तीसगढ़ विधानसभा के आठवें दिन की शुरू होते ही दिवंगत सदस्यों की निधन सूचना में देरी पर विधायकों ने सवाल उठाया। स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने देर से निधन सूचना मिलने पर नाराजगी जताते हुए दोषी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रशासन को स्पष्ट निर्देश होने के बाद विधानसभा को दिवंगतों की निधन सूचना देरी से मिल रही है। इस पर आसंदी की ओर से व्यवस्था आनी चाहिए। स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मैने पूर्व में भी शासन को स्पष्ट निर्देश दिया गया था। किसी भी पूर्व सदस्य की निधन की सूचना देर से मिलना बहुत आपत्तिजनक है। दरअसल, डॉ. देवचरण मधुखर के निधन की सूचना मिलने में देरी हुई। अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व विधायक डॉ. मधुकर का निधन 12 फरवरी को हुआ था। इस बात की जानकारी सदन को 4 मार्च को प्राप्त हुई।

5-8 वीं की केंद्रीयकृत परीक्षाओं की बाध्यता हटाने आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने 5-8 वीं की केंद्रीयकृत परीक्षाओं की बाध्यता हटाने का आदेश जारी कर दिया है। अवर सचिव आरपी वर्मा ने सभी डीईओ को आदेश जारी कर कहा है कि जो निजी स्कूल इच्छुक हैं उन्हें केंद्रीकृत परीक्षा में सम्मिलित किया जाए। सभी के लिए अनिवार्य नहीं होगा। किसी को भी बाध्य नहीं किया जाए। बता दें कि करीब 5 हजार से अधिक स्कूलों ने केंद्रीयकृत परीक्षा आयोजन पर अपनी सहमति दे दी है।

अवर सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक संदर्भित पत्र दिनांक 03.12.2024 द्वारा कक्षा 5वीं एवं छवीं की केन्द्रीकृत परीक्षा के निर्देश दिये गये थे। अशासकीय विद्यालय प्रबंधन समिति तथा पालक संघ द्वारा इसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिकाएं (डब्ल्यूपीसी 899/2025, डब्ल्यूपीसी 1145/2025 एवं डब्ल्यूपीसी 1158/2025) दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2025 को निर्णय पारित किया गया।

जो अशासकीय विद्यालय सत्र 2024-25 की कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, उन्हें इस सत्र इस छूट दी जाये। जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी अशासकीय विद्यालय को सत्र 2024-25 की कक्षा 5वीं एवं हवीं की केन्द्रीकृत परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बाध्य न किया जाये। ऐसे अशासकीय विद्यालय जो सत्र 2024-25 की कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाये।

भूपेश बघेल के जासूसी के आरोप पर उप मुख्यमंत्री शर्मा का पलटवार

कहा- एकदम निराधार और बेकार की बातें हैं

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के फोन सर्विलॉन्स होने वाले आरोप पर सवाल किया कि क्यों करेंगे? क्या मसला है, कोई बात ही नहीं है, जबरदस्ती की बातें हैं। एकदम निराधार और बेकार की बातें हैं, ना कोई संभावना।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी बजट से डर गए हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। निरर्थक बातें कर रहे हैं। इस पर जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उनके फोन टेप होने वाले बयान पर कहा कि कभी हुआ था, कभी कहा भी था। लगा तब कहा था, लेकिन ऐसी सुबह उठकर नहीं कहा था। कांग्रेस का यह बोलना औचित्यपूर्ण विषय है।

दरअसल, एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जासूसी के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मेरा फोन भी सर्विलांस में है, मेरे बगल में खुफिया तंत्र के कर्मचारी खड़े रहते हैं, खुफ्क के कर्मचारी पत्रकारवार्ता में मेरी बात को सुनते हैं।

वहीं विपक्ष के बहिर्गमन को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र है। बीजेपी लोकतंत्र का सम्मान करने वाले पार्टी है। जनादेश जो आ गया, सो आ गया। विष्णु देव की सरकार से नहीं सक पा रहे तो ईवीएम के बाद दूसरा शिगुफा छोड़ रहे हैं। बीजेपी की सरकार ना रुकेगी, ना रफ्तार रुकेगा।

डीएमएफ घोटाला: कोर्ट में पेश हुए रानू, सौम्या और सूर्यकांत

रायपुर। डीएमएफ घोटाला मामले में विशेष कोर्ट ने तीनों आरोपी सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी को ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंप दिया है। आरोपियों को 10 मार्च तक ईओडब्ल्यू रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। डीएमएएफ घोटाले में अब पांच आरोपी सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, माया वॉरियर, मनोज द्विवेदी ईओडब्ल्यू की रिमांड पर रहेंगे।

बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि ईओडब्ल्यू रिमांड खत्म होने के बाद आज तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। आज फिर ईओडब्ल्यू ने 10 मार्च तक रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए तीनों आरोपियों को रिमांड पर सौंपा है।

आरोप पत्र में अब तक हुई जांच के हवाले से ईडी ने आकलन दिया है कि डीएमएफ घोटाला 90 करोड़ 48 लाख रुपये का है। आरोप पत्र में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, महिला बाल विभाग की अफसर रहीं माया वारियर, ब्रोकर मनोज कुमार द्विवेदी समेत 16 आरोपितों के नाम हैं। ईडी की जांच में पता चला कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में मनोज कुमार द्विवेदी ने रानू साहू और अन्य अधिकारियों से मिलीभगत की। अपने एनजीओ उदगम सेवा समिति के नाम पर कई डीएमएफ ठेके हासिल किए थे। अधिकारियों को टेंडर की राशि का 40 प्रतिशत तक कमीशन दिया था।

ईडी की रिपोर्ट के आधार पर डीएमएफ घोटाले में ईओडब्ल्यू ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है। केस में यह तथ्य सामने आया कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड कोरबा के फंड से टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया। जांच में पाया गया कि टेंडर राशि का 40त्न सरकारी अफसर को कमीशन के रूप में दिया गया है।

गुरूदर्शन मेला में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

रायपुर। बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली और कर्मस्थली गिरौदपुरी में आयोजित गुरूदर्शन मेला अपनी भव्यता और आस्था के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। 04 से 06 मार्च तक चलने वाले इस मेले में छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत से हजारों श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

मुख्यमंत्री साय ने इस बार मेले को भव्य स्वरूप में आयोजित करने के लिए 50 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है, जो पूर्व में 25 लाख रुपए थी। इसके साथ ही, मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थायी शेड के निर्माण की भी घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री साय ने स्वयं गुरू गद्दी का दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की और मेले की भव्यता बढ़ाने और श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए मेला बजट को दोगुना करने के साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री श्री साय की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण एवं माप-जोख करने के निर्देश दिए हैं। गुरुदर्शन मेले में श्रद्धालुओं को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा सहायता केंद्रों की संख्या 2 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है और एंबुलेंस की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 की गई है। नि:शुल्क भोजन सेवा को भी विस्तार देते हुए अब 24 स्थानों पर 212 समूहों द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो पहले 20 स्थानों पर 175 समूहों द्वारा संचालित थी। पेयजल व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है, जिसमें स्थायी नल कनेक्शन की संख्या 110 से बढ़ाकर 195 कर दी गई है और पानी टैंकरों की संख्या 8 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम की संख्या 3 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है, सुरक्षा बलों की संख्या 450 से बढ़ाकर 1150 की गई है और पहली बार 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी नियमित मॉनिटरिंग हो रही है।सुरक्षाकर्मियों को 130 वायरलेस सेट भी प्रदान किए गए हैं। अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब 1 के बजाय 3 अग्निशमन वाहन तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। मेले में विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है, जिसमें ट्रांसफार्मरों की संख्या 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है और विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में बैकअप जनरेटर की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए शौचालयों की संख्या 4 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है, स्नानागार की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 की गई है, और अतिरिक्त रूप से 80 सीटर स्थायी शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या 80 से बढ़ाकर 291 कर दी गई है ताकि मेले में स्वच्छता बनी रहे।

इस वर्ष पहली बार गिरौदपुरी मेला डॉट कॉम नामक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को मेला स्थल की जानकारी, आवश्यक मार्गदर्शन और अन्य आवश्यक सेवाओं की ऑनलाइन जानकारी मिल सके। इससे श्रद्धालु यात्रा संबंधी सूचनाएं, पार्किंग व्यवस्था, धार्मिक स्थलों की जानकारी और अन्य सुविधाओं की पूरी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

क्या छत्तीसगढ़ में बिना दूल्हे की बारात की परंपरा है: महंत

■ **मंत्री बोले - नेताजी दिल्ली मुंबई में हुए इन्वेस्टर मीट की ओर इशारा कर रहे हैं**

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने उद्योग मंत्री लखन देवांगन को घेरते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के इन्वेस्टर मीट के आयोजनों, उसमें हो रहे खर्च और निवेश की स्थिति पर सीधे पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ में बिना दूल्हे की बारात की परंपरा है? इस पर मंत्री देवांगन ने उनका इशारा समझते हुए कहा कि नेताजी दिल्ली मुंबई में हुए इन्वेस्टर मीट की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके पहले भी सरकारें ऐसे सम्मेलन आयोजित कर निवेशकों को आमंत्रित करती रही है और हमारे पहले आयोजन के बाद 47 हजार करोड़ के 31 निवेश के प्रस्ताव से अब तक मिले है और प्रश्न लगने के बाद से अब तक 1.32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।

नेता प्रतिपक्ष डॉ महत ने कहा कि मंत्री जी को जितना सिखाया उन्होंने बता दिया। मेरा आशय यह है कि उद्योग के लिए स्थल, भूमि का चयन हुआ नहीं है, उद्योग लगाना चाहते है या नहीं यह तय नहीं हुआ और आयोजन कर रहे। महंत ने कहा कि 31 निवेश के प्रस्ताव नहीं है, इनविटेशन टू इनवेस्ट लेटर है। ये आए नहीं है पत्र लिख लिखकर बुलाए गए हैं। मंत्री जी इतनी जल्दी मत करिए। पहले जमीन, पानी बिजली कहां कैसे देंगे तय कर लें तब आमंत्रण दें। मंत्री देवांगन ने कहा कि भूमि, निवेशकों की मांग पर सरकार के लैंड बैंक या जरूरत पर निजी भूमि भी देते हैं। और 31 निवेशकों में से 4 ने भूमि चिन्हित कर ली है। इन्हे नवा रायपुर और पथरिया मुंगेली में दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत ने दिल्ली मुंबई के मीट आयोजन में हुए खर्च 1.3 और 1.61 करोड़ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह किसी इवेंट कंपनी को दिया गया या अफसरों ने किया। मंत्री ने कहा कि पहले भी खर्च होते रहे हैं। उद्योगपतियों को बुलाते हैं तो उनके खाने पीने का खर्च होता ही है।

Public Works Department
Sector-19, North Block, Naya Raipur (C.G.)

E-Procurement Tender Notice
E-mail: tenders-pwd.cg@gov.in

NIT No. 323/TC/EinC/PWD/2024-25 Dated- 03.03.2025

The Engineer-in-Chief, Public Works Department on behalf of Governor of Chhattisgarh invites percentage rate bids on electronic tendering system under RCPLWE RRP-III in the district of Sukma for construction of 02 Roads with estimated cost amounting Rs 345.92 Lacs including their maintenance for five years from the contractors registered with unified registration system (e-registration) in Chhattisgarh. Non registered bidders may submit bid; however the successful bidder must get registered in appropriate class under "Unified Registration System (e-Registration) of Chhattisgarh before signing the agreement.

The bid document shall be available to bidders online free of cost and should be submitted online e-procurement system of government of Chhattisgarh in https://eproc.cgstate.gov.in. Bids form will be available on the website from 05.03.2025 and may be submitted up to 17:00 Hrs. on 21.03.2025

For participating in bidding process, bidders are required to register in the above web-site with nominal fee of Rs 500/- to be paid onine to service provider. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from authorized certifying authorities.

The bidders are required to submit (a) original bid security in approved form and (b) original affidavit duly verified and notarized as per clause 4.4 B (a) (ii) and 4.4 B (c) to Chief Engineer, Tender Cell, First Floor, Nirman Bhawan, PWD, North Block, Sector-19, Naya Raipur Atal Nagar (C.G.) 492-002 as per provisions of bid document through Speed/ Registered post, failing which the bids shall be declared non-responsive.

Detailed schedule of important dates may be seen on notice board of offices and also available on website of Public Works Departmenthttp://pwd.cg.nic.in

G-242505756/8

Chief Engineer
(Central Tender Cell)
Office of Engineer-In-Chief
PW.D. Nava Raipur Atal Nagar (C.G.)

वर्चस्व पर संकट का कवच बनती हिंदी विरोध की राजनीति

उमेश चतुर्वेदी

हिंदी को लेकर तमिलनाडु की राजनीति का आक्रामक होना कोई नई बात नहीं है। हिंदी के विरोध में जिस तरह स्टालिन ने रोजाना आधार पर मोर्चा खोल रखा है, वह 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की याद दिला रहा है। संवैधानिक प्रावधानों की वजह से 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजभाषा के तौर पर जिम्मेदारी संभालनी थी, जिसके विरोध में सीए अन्नादुरै की अगुआई में पूरी द्रविड़ राजनीति उतर आई थी। तब हिंदी विरोध के मूल केंद्र में तमिल उपराष्ट्रीयता थी। उसके लिए तब यह साबित करना आसान था कि उस पर हिंदी थोपी जा रही है। तब आज की तरह सूचना और संचार की सहूलियतें नहीं थीं, तब दक्षिण और उत्तर के बीच आज की तरह सहज संचार नहीं था, तब आज की तरह मीडिया का इंटरनेटी वितान नहीं था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। लिहाजा इस संदर्भ में स्टालिन के मौजूदा हिंदी विरोध की तह में जाना जरूरी हो जाता है। चाहे तमिलनाडु का निवासी हो या फिर उत्तर भारत के किसी हिंदीभाषी इलाके का, उसके हाथ में अगर फोन है, उसमें अगर इंटरनेट का कनेक्शन है तो तय है कि उसकी उंगलियों के नियंत्रण में हिंदी और अंग्रेजी ही नहीं, दुनियाभर की भाषाएं हैं। इसलिए कम से कम सूचना और संचार के ऐसे माध्यमों पर किसी सरकार की वजह से भाषायी बंधन आज के दौर में हो भी नहीं सकता। इंटरनेट क्रांति के पहले भाषाओं के विस्तार में बाजार ने जो भूमिका निभाई, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज का बाजार वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के पंखों के सहारे कहीं और तेजी से फैल तो रहा ही है, फल-फूल भी रहा है। इसलिए हिंदी ही नहीं, किसी भी भाषा का विरोध अब दुनिया के किसी भी कोने में पूरी तरह न तो सफल हो सकता है और कोई दीवार उसे रोक सकती है। बेशक तमिलनाडु भाषायी स्तर पर अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन वह भी हमारे देश का हिस्सा है। मौजूदा स्थिति में तेजी से विकसित होता राज्य है और उसे अपने उत्पादन केंद्रों के लिए कामगारों की जरूरत है। जिसकी आपूर्ति उत्तर भारत के ही राज्य करते हैं। उसके निजी शैक्षिक केंद्रों के लिए विद्यार्थियों की भी जरूरत है। उत्तर भारत की जो शैक्षिक स्थिति है, उसकी असलियत सबको पता है। इस वजह से उत्तर भारतीय छात्रों की आवक भी तमिलनाडु में खूब है। ऐसे माहौल में वैसे तो हिंदी विरोध के औचित्य पर ही सवाल है। फिर भी स्टालिन विरोध कर रहे हैं तो उसके अपने कारण हैं। संचार और सूचना क्रांति और तेज आवागमन के चलते भाषायी स्तर पर तमिलनाडु की स्थिति तीन-चार दशक पहले जैसी नहीं है। वहां हिंदी बोलने वालों की संख्या भले कम हो, लेकिन उसे समझने और हिंदी में आने वाले सवालों का जवाब देने या प्रतिक्रिया में सौदा-सुलफ मुहैया कराने वालों की तादाद बढ़ी है। हिंदी या कोई अन्य भाषी वैसे भी तमिल संस्कृति को इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तमिल संस्कृति और भाषा दुनिया की पुरानी संस्कृतियों में से एक है और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तमिल लोग अपनी संस्कृति और भाषा से नेह-छोह ही नहीं रखते, उसका शिद्दत से सम्मान भी करते हैं। फिर तमिलनाडु की ऐसी स्थिति नहीं है कि दिल्ली, जालंधर, सूरत, लुधियाना, मुंबई की तरह तमिलनाडु के शहरों में हिंदीभाषियों की बाढ़ आ जाएगी। वैसे एक बारगी मान लें कि जिन जगहों का जिक्र हुआ है, वहां हिंदीभाषियों की बाढ़ होने के बावजूद क्या वहां की स्थानीय संस्कृति और भाषाओं पर संकट आया। निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। दरअसल होता यह है कि बाहर से आया व्यक्ति स्थानीय संस्कृति और समाज के लिहाज से वहां व्यवहृत भाषा को अपने सामाजिक और सार्वजनिक कामकाज की भाषा बनाता है।

यूरोप के साथ भारत के मजबूत होते रिश्ते

अनिल त्रिगुणायत

यह उम्मीद जतायी जा रही है कि इस साल ब्रिटेन और यूरोपीय संघ, दोनों के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होने वाला है. ब्रिटेन के साथ, जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत फिर से बहाल हो चुकी है। इससे अगले 10 वर्षों में दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 20 अरब डॉलर का दोगुना या तीन गुना होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच इस बारे में वार्ता जनवरी, 2013 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। मुक्त व्यापार समझौते में दो देश व्यापार किये जाने वाले अधिकतम सामान पर सीमा शुल्क को या तो समाप्त कर देते हैं या काफी कम कर देते हैं। वे सेवाओं और द्विपक्षीय निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के मानदंडों को भी आसान बनाते हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि भारत और ब्रिटेन सिर्फ एफटीए पर बात नहीं कर रहे। दोनों देश इसके साथ-साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआइटी) और दोहरे अंशदान कन्वेंशन समझौते पर भी बातचीत कर रहे हैं। इस बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर गये हैं।

ब्रिटेन के अलावा यूरोपीय संघ से भी मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही है। यूरोपीय संघ फिलहाल दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश में है। इसी के तहत संघ की अध्यक्ष उर्सूला बॉन डेर लेयेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 27-28 फरवरी को कुल 27 में से 22 कैबिनेट सहयोगियों के साथ, जिन्हें इयू कॉलेज ऑफ कमिशनर्स कहा जाता है, भारत यात्रा पर आयी थीं। उर्सूला बॉन की यह तीसरी भारत यात्रा थी। सबसे पहले वह अप्रैल, 2022 में द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा पर नयी दिल्ली आयी थीं। दूसरी बार सितंबर, 2023 में वह जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आयी थीं। जबकि इयू कॉलेज ऑफ कमिशनर्स की यह पहली भारत यात्रा थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने से पहले ही उर्सूला बॉन ने, जिनका इयू की अध्यक्ष के तौर पर यह दूसरा कार्यकाल है, यूरोप से बाहर आर्थिक साझेदारी के लिए भारत को चुनने का निर्णय कर लिया था। इसका कारण आर्थिक मोर्चे पर भारत की मजबूती और इसकी शानदार लोकतंत्रिक छवि है।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर पर व्यापक चर्चा की। अपनी यात्रा के दौरान उर्सला बॉन ने कहा कि यूरोपीय संघ जापान और दक्षिण कोरिया के साथ किये गये समझौतों की तरह भारत के साथ भविष्य में सुरक्षा साझेदारी की संभावनाएं तलाश रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष तक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रहे हैं, जो विश्व स्तर पर अपनी तरह का सबसे बड़ा समझौता होगा।

यूरोपीय संघ के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों के तीन दशक पूरे होने वाले हैं। हालांकि भारत उन शुरुआती देशों में था, जिसने 1963 में यूरोपीय संघ के साथ, जो तब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी (इइसी) के नाम से जाना जाता था, अपना रिश्ता शुरू किया था। लेकिन शीतयुद्ध के दौर में जब भारत तत्कालीन सोवियत संघ की ओर झुकता चला गया, तब यूरोपीय संघ के साथ उसका रिश्ता कायदे से आकार ही नहीं ले पाया। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में भारत के रिश्ते यूरोपीय संघ से बनने शुरू हुए। दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी 2004 में शुरू हुई और इन्होंने 2007 में एफटीए पर बातचीत आरंभ की। हालांकि 2013 में एफटीए पर इनकी बातचीत टूट गयी और सिर्फ रणनीतिक साझेदारी चलती रही। मोदी सरकार ने 2022 में यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर वार्ता फिर शुरू की।

हालांकि यूरोपीय संघ के साथ सिर्फ मुक्त व्यापार समझौता काफी नहीं है, दोनों तरफ से आव्रजन और आवाजाही भी जरूरी है, खासकर भारत की तरफ से। अब बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड दो से आठ मार्च तक भारत यात्रा पर हैं। बेल्जियम और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत की आजादी के एक महीने के बाद ही बेल्जियम ने हमारे साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया था। हीरे दोनों देशों के बीच के आर्थिक संबंधों की आधारशिला बने हुए हैं। बेल्जियम के आर्थिक मिशन पर आयीं राजकुमारी के साथ 335 सदस्यों और 180 कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल है। इस दौरान नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, पर्यावरण, जीवन विज्ञान और इस्पात डीकार्बनाइजेशन जैसे मुद्दों पर कम से कम 14 सम्मेलन और सेमिनार होने हैं। इस बीच बेल्जियम के राजदूत ने एएनआइ को बताया, 'हम यूरोपीय संघ और भारत तथा भारत और बेल्जियम के बीच और अधिक गहन तथा रणनीतिक संबंध की ओर बढ़ रहे हैं। हमें दुनियाभर में विश्वसनीय भागीदारों की आवश्यकता है। भारत में हर वर्ष पांच से सात प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हो रही है। इसलिए भारत हमारी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है।' इस वर्ष भारत और बेल्जियम के बीच रक्षा समझौता होने की उम्मीद जतायी जा रही है।

ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों में अंतर है। ब्रिटेन के साथ हमारे पारंपरिक संबंध हैं और उसके साथ अधिक समस्या नहीं है। लेकिन यूरोपीय संघ का बाजार संरक्षणवादी है। इएसजी (इन्वायर्नमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस) और सीबीडी (कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी) जैसे उसके सख्त मानकों का पालन कर पाना कठिन है। यानी वह उत्पादों को पर्यावरण और दूसरी कसौटियों पर कसकर देखता है। यूरोपीय संघ ने इएसजी से जुड़े कई कानून बनाये हैं, जिनका मकसद निवेशकों और आम लोगों को कंपनियों के पर्यावरण, सामाजिक मूल्य और शासन से जुड़े प्रदर्शन के बारे में जानकारी देना है। चूंकि यूक्रेन मुद्दे पर यूरोप का रुख अमेरिका से अलग दिखता है, ऐसे में, यह माना जा रहा है कि यूरोप संभवतः भारत जैसे बड़े बाजारों के नजदीक आये। यह एक हद तक सच है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अमेरिकी मदद के बगैर यूरोप यूक्रेन युद्ध का खात्मा नहीं कर सकता, न ही वह जेलेंस्की को मदद देने की स्थिति में है। ऐसे ही, यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भारत ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति से परेशान होकर यूरोप की तरह झुक जायेगा। यह संभव नहीं है। भारत जब भी यूरोप के साथ जायेगा, वह अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ता बनाते हुए ही जायेगा। यानी न तो भारत के लिए अमेरिका की अनदेखी संभव है और न ही यूरोप के लिए।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

अर्थात् (ख) अनन्त शिर वाले विराट् पुरुष से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। उस ब्रह्मा से गुणों में पिता के समान अत्रि पुत्र हुये। अत्रि की दृष्टि से अमृतमय चन्द्रमा पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उसको ब्राह्मणों औषधियों और नक्षत्रों का अधिपति नियत किया और उसने तीनों लोकों को जीत कर राजसूय यज्ञ किया। एक बार घमण्ड से चन्द्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को छीन लिया। गुरु ने बार बार याचना की तब भी उसने तारा को न लौटाया। इसी कारण से देवता और दानवों में घोर संग्राम उन गया। इधर शुक्राचार्य ने बृहस्पति के द्वेष से चन्द्रमा को असुरों के पक्ष में मिला लिया। उधर अंगिरा से प्राप्तविद्य होने के कारण भूतगण सहित शिव भगवान् ने अपने गुरुपुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया और देवगण सहित इन्द्र ने भी अपने गुरु की सहायता की। इस तरह दोनों पक्ष बन्ध जाने पर परस्पर संघर्ष से देव और दानवों का विनास हो गया। यह तारागणों का पारस्परिक युद्ध समझना चाहिये। अंगिरा के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने चन्द्रमा को झिड़क कर तारा स्वपति बृहस्पति को दिलवा दी। परन्तु बृहस्पति ने तारा को सगर्भा जानकर कहा कि हे दुर्बुद्धे! मेरे क्षेत्र में दूसरे के बोये बीज को तू जल्दी निकाल, नहीं नो तुझे भस्म कर डालूंगा। मुझे सन्तान की इच्छा नहीं है, तू स्त्री है इसीलिये अवध्य समझता हूं। तारा ने लज्जित होकर सोने के समान कान्ति बाले पुत्र को जना तो इसे देख बृहस्पति और चन्द्रमा दोनों ने ही लेने की इच्छा की, और यह बालक मेरा है तुम्हारा नहीं ऐसा कहकर परस्पर झगड़ा करने लगे।

तब ब्रह्मा जी ने एकान्त में बुला कर सान्त्वना देते हुये तारा से पूछा और उसने धीरे से चन्द्रमा का ऐसा बताया। तब पुत्र चन्द्रमा ने ग्रहण किया और ब्रह्मा जी ने उसका नाम बुध रक्खा।

क्रमशः ...

गोविंद बल्लभ पंत

अनन्या मिश्रा

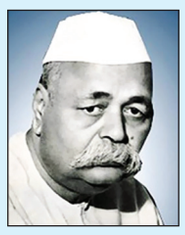

उत्तर प्रदेश में एक दौर ऐसा भी था, कांग्रेस पार्टी का एकछत्र राज्य हुआ करता था। लेकिन यूपी की सियासत मंडल और कमंडल के भूचाल से 360 डिग्री घूम गई। वैसे तो यूपी की राजनीति और उसके निर्माण में कई शख्सियतों और नेताओं का हाथ रहा, लेकिन आधुनिक यूपी के निर्माण का श्रेय गोविंद बल्लभ पंत को जाता है। बता दें कि आज ही के दिन यानी की 07 मार्च को गोविंद बल्लभ पंत का निधन हो गया था।

गोविंद बल्लभ पंत भारत के दूसरे गृह मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय संविधान में हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने और जमींदारी प्रथा को खत्म कराने में उन्होने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने हिंदू संहिता विधेयक पारित कराया और हिंदू पुरुषों के लिए एकपत्नीत्व अनिवार्य बना दिया था। उन्होंने हिंदू महिलाओं को तलाक और वंशानुगत संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार दिए थे। भारत रत्न का सम्मान उनके ही गृह मन्त्रित्व काल में शुरू किया गया था, यही सम्मान उन्हें सन 1947 में उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रदान किया गया था।

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में 10 सितंबर 1887 को गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। शुरूआती शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर काशीपुर में वकालत का कार्य करने लगे। पंत की गिनती अच्छे वकीलों में की जाती थी।

इतना ही नहीं पंत को कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तर्ज पर गोविंद बल्लभ पंत ने एक ऐसा ही आंदोलन शुरू किया था। जिसके कारण ब्रिटिश सेना ने उन्हें जेल भेज दिया था। इसके अलावा उन्होंने साइमन कमीशन का भी बहिष्कार किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उनको जेल में रहना पड़ा। कांग्रेस कमिटी के अन्य सदस्यों के साथ मार्च 1945 तक वह अहमदनगर किले में तीन साल तक रहे।

गोविन्द बल्लभ पंत को भूमि सुधारों में बेहद रुचि थी उन्होंने 21 मई सन 1952 को जमींदारी उन्मूलन कानून को प्रभावी बनाया था। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी विशाल योजना नैनीताल तराई को आबाद करने की थी। प्रशासनिक कुशलता, न्यायप्रिय सुधारों से उन्होंने सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य की हालत को एकदम दुरुस्त किया था। उनकी उपलब्धियों में हिंदू संहिता विधेयक पारित कराना और हिंदू पुरुषों के लिए एकपत्नीत्व अनिवार्य बनाना था। उन्होंने हिंदू महिलाओं को तलाक और वंशानुगत संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार दिए थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद उन्हें गृह मंत्रालय का दायित्व दिया गया था। गृह मंत्री के रूप में भारत को भाषा के आधार पर राज्यों में विभक्त करना व हिंदी को राजभाषा के तौर सम्मान दिलवाने में उनका मुख्य योगदान रहा था। 7 मार्च सन 1961 को हृदयाघात से जूझते हुए उनका देहावसान हो गया था।

बराबरी का शुल्क और भारत के पास विकल्प

अमिता बत्रा

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभालते ही जो सबसे अहम मगर उथल-पुथल मचाने वाली घोषणाएं की हैं, उनमें एक है व्यापारिक साझेदारों पर 'बराबरी का शुल्क'। व्हाइट हाउस से 13 फरवरी 2025 को जारी विज्ञप्ति में व्यापक ब्योरा देते हुए बताया गया है कि अमेरिका पांच कसौटियों का इस्तेमाल कर देखेगा कि उसके व्यापार साझेदार उसके साथ बराबरी का बरताव कर रहे हैं या नहीं। इसमें अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाले शुल्क के साथ व्यापार की राह में दूसरी बाधाएं, सब्सिडी और/अथवा कोई उपाय और साझेदार देश में विनिमय दरों, करों अथवा नियामकीय जरूरतों से जुड़ी वे नीतियां शामिल हैं, जो अमेरिकी प्रशासन की नजर में भेदभाव करने वाली हैं या अमेरिकी कंपनियों, कर्मचारियों और/अथवा उपभोक्ताओं को बाजार में बिल्कुल नहीं आने देतीं या कम आने देती हैं।

अमेरिका अपने हरेक व्यापार साझेदार के साथ लगभग 13,000 वस्तुओं का व्यापार करता है और इनमें से हर किसी को ऊपर बताई गई कसौटियों पर कसना लगभग असंभव लगता है। इसलिए इस बात की अटकलें जमकर लगाई जा रही हैं कि शुल्क का मूल्यांकन किसी खास उत्पाद के लिए होगा या समूचे उद्योग अथवा क्षेत्र का औसत शुल्क देखा जाएगा। सवाल यह भी है कि अमेरिका एकतरफा कार्रवाई करेगा या वह भी परिधान और वस्त्र जैसे उन क्षेत्रों अथवा उद्योगों में शुल्क घटाएगा, जिनमें वह दूसरों से ज्यादा शुल्क लगाता है। चूंकि अभी तक इन सवालों और इनसे जुड़े दूसरे कई सवालों का कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए अभी इंतजार करके यह देखना शायद सबसे सही होगा कि अप्रैल और उसके बाद बराबरी का शुल्क किस तरह लगाया जाता है। हां, इस बीच व्यापार के दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

फिर भारत के पास विकल्प क्या हैं? भारत ने अभी तक एहतियातन पहले ही कदम उठाने का तरीका अपनाया है। यह मेक्सिको या कनाडा के रुख से उलट है। दोनों देशों ने उत्पादों पर 25 फीसदी शुल्क लगने के बाद वादा किया कि अमेरिका में अवैध घुसपैठ और फेंटनाइल ओपिऑइड की तस्करी पर रोक लगाने के लिए वे अपनी-अपनी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाएंगे। एक तरह से यह सीमा सुरक्षा बढ़ाने की उनकी नीतियों का विस्तार ही था।

उनसे उलट भारत ने अमेरिकी आयात पर लगाए जा रहे शुल्क की ट्रंप द्वारा की गई आलोचना का जवाब दिया है। फरवरी 2025 में पेश बजट में 1,600 सीसी इंज वाली मोटरसाइकल समेत कुछ उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क कम कर दिए गए। इसके कुछ दिन बाद ही बर्बेन व्हिस्की पर आयात शुल्क घटा दिया गया, जो जाहिर तौर पर अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया। इसके बाद भी ट्रंप भारत की शुल्क दरों पर टिप्पणियां करते रहे और बराबरी के शुल्क के मामले में भारत के साथ किसी तरह की रियायत बरतने का संकेत भी उन्होंने नहीं दिया। ध्यान रहे कि भारत उन शीर्ष 15 व्यापार साझेदारों में है, जिनके साथ अमेरिका निर्यात से ज्यादा आयात करता है यानी व्यापार घाटे में है।

भारत अभी अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की तैयारी कर रहा है मगर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी व्यापार नीति की चुनौतियों से निपटने के लिए शायद इतना काफी नहीं होगा। मेक्सिको और कनाडा पर शुल्क लगाकर ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वह अपने पहले कार्यकाल में हुए अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते को ताक पर रखने के लिए तैयार हैं। ऐसे में भारत को अपने निर्यात बाजारों तथा उत्पादों में विविधता लाकर व्यापार के अवसर लपकने होंगे। वह दूसरे देशों द्वारा हाल में उठाए गए व्यापारिक कदमों से सबक ले सकता है। उदाहरण के लिए व्यापार में विविधता लाने की नीति के तहत कुछ देशों ने मुक्त व्यापार समझौतों के लिए अपनी बातचीत तेज कर दी है।

मेक्सिको और यूरोपीय संघ ने हाल ही में अपने पिछले व्यापार समझौते को बेहतर बनाया है। इसके तहत दोनों ने कर में काफी कटौती की है और पर्यावरण के अनुकूल तौर-तरीकों तथा हरित वृद्धि समेत कई उच्च मानक वाले इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह यूरोपीय संघ और मर्कोसुर (उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील) के बीच काफी समय से अटके व्यापार समझौते को दिसंबर 2024 में अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने की संभावना के बीच इस समझौते पर बातचीत तेज की गई थी। समझौते में केवल शुल्क की बात नहीं है बल्कि पर्यावरण मानक और दुर्लभ खनिज भी शामिल किए गए हैं।

यूनाइटेड किंगडम ने भी यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा शुरू कर दी है। इससे पहले 2024 में उसने व्यापक और प्रगतिशील प्रशांत पार साझेदारी (सीपीटीपीपी) की सदस्यता हासिल की। आसियान देशों की बात करें तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और सीपीटीपीपी जैसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौते उन्हें व्यापार की पैठ और भी बढ़ाने के मौके देते हैं। भारत के उलट कुछ आसियान देशों को अभी अमेरिका में जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज के जरिये रियायत के साथ बाजार में जाने का मौका मिल रहा है।

भारत ने भी यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार वार्ता बहाल करने की घोषणा की है मगर बातचीत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अभी और काम करना होगा। शुल्क वास्तव में कम करने हैं तो उनमें अधिक व्यवस्थित तरीके से कटौती करनी होगी। फरवरी में आए बजट में जिन कमोडिटी के लिए मूल सीमा शुल्क कम किया गया, उनमें से ज्यादातर पर अलग से उपकर लगाया गया है, जिस वजह से शुल्क की दर पहले जितनी ही रही। अमेरिका से बराबरी का शुल्क लगने का खतरा देखते हुए भारत के लिए अपनी औसत शुल्क दरें चरणबद्ध तरीके से घटाने और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बराबर लाने पर विचार करने का यह अच्छा मौका है।

इस बार के बजट में आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि की समीक्षा करने की बात कही गई है। यह काम जल्दी कर लेने से भारत को अधिक गहन व्यापार समझौते करने और निर्यातोन्मुखी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने में मदद मिलेगी। पर्यावरण से जुड़े मसलों पर भी भारत को बातचीत के लिए उचित रुख अपनाना होगा क्योंकि आजकल व्यापार जलवायु परिवर्तन और कामगारों की स्थितियों तथा अधिकारों पर राजनीतिक आलोचना जैसी तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच होता है। कृषि एवं वनोपज निर्यात की अधिक हिस्सेदारी वाली लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं ने यूरोपीय संघ और मरकोसुर मुक्त व्यापार संधि में इन सभी मसलों पर सफलतापूर्वक सौदा किया है, जिससे भारत को काम के सबक मिल सकते हैं। साथ ही भारत को सीपीटीपीपी में भागीदारी की शुरुआत भी करनी चाहिए क्योंकि उसके प्रावधान आधुनिक व्यापार के लिहाज से बनाए गए हैं और उसके सदस्यों की बढ़ती संख्या बता रही है कि जल्द ही वह नियमों पर आधारित सबसे बड़ा व्यापार समूह बन सकता है।

बहुपक्षीय मोर्चे पर भी भारत का एक नजरिया होना चाहिए। हमें नियम आधारित वैकल्पिक व्यापार व्यवस्था तैयार करने के सामूहिक प्रयासों में अधिक योगदान करना होगा। यह जरूरी है क्योंकि विश्व व्यापार में निष्पक्षता का सिद्धांत बड़ी संस्था के जरिये ही निभाया जा सकता है। भारत अब तक प्लूरीलेटरल (जिनके सदस्यों की संख्या दो से कुछ ही ज्यादा होती है) समझौतों या समूहों से दूर रहा है। इस पर उसे पुनर्विचार करना पड़ सकता है और शायद अब देशों को कुछ पैमाने तय कर प्लूरीलेटरल की परिभाषा नए सिरे से गढ़नी चाहिए। उसमें शामिल होना या न होना किसी भी देश की मर्जी पर छोड़ जा सकता है। इसलिए भारत को रणनीतिक व्यापार नीति बनानी चाहिए, जो बहुमुखी हो और आज के विश्व व्यापार में आ रही चुनौतियों से निपट सके।

आज का इतिहास

1952 वेस्टइंडीज के ऑलराइंडर सर विवियन रिचडर्स का जन्म हुआ था। इनके नाम 121 टेस्ट में 8,540 रन और 32 विकेट तथा 187 वनडे में 6,721 रन और 118 विकेट हैं।

1959 अमेरिकी पायलट मेल्विन सी गार्लोव जेट विमानों से एक लाख मील की दूरी तय करने वाले पहले पायलट बने।

1965 अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन-सेलम से मॉन्टगोमरी, अलबामा तक मार्च करने वाले नागरिक अधिकार आंदोलनकारियों को पुलिस ने रविवार को खूनी तरीके से बर्खास्त कर दिया।

1969 इसरायल ने 70 साल की गोल्डा मेयर को प्रधानमंत्री चुना था।

1985 एड्स का पहला एंटीबॉडी परीक्षण एलिसा-टाइप टेस्ट शुरु किया गया।

1985 अफ्रीका के लिए सुपरग्रुप यूएसए द्वारा चैरिटी सिंगल वी आर द वर्ल्ड जारी की गई थी, और इसकी 20 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकेंगी।

1992 माइकोल स्टीवेन्सन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक समय में 200 मीटर की तैराकी में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का कारनामा किया (2:06:78)

1993 टोड ब्रिज, प्रसिद्ध अभिनेता, एक किरायेदार को छुरा घोंपने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

1994 8 वें अमेरिकी कॉमेडी अवार्ड की घोषणा की गई है। गाजर टॉप विजेता बनता है।

1994 लाइबेरिया के राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

1995 डॉलर, 1.5330 इच गिल्डर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।

1995 मौत की सजा पाने वाला न्यूयॉर्क दुनिया का 38 वां राज्य है।

2009 नासा ने ब्रम्हांड में पृथ्वी जैसे ग्रह और उनपर जीवन को तलाशने के लिए केप कनावेरल से केप्लर नाम की एक दूरबीन को अंतरिक्ष में छोड़ा था।

2009 केप्लर अंतरिक्ष वेधशाला, जिसे पृथ्वी-जैसे किसी दूसरे तारे की परिक्रमा करने के लिए डिज़ाइन किया गया, लॉन्च किया गया।

2010 इराकी मतदाताओं ने संसदीय चुनाव में भाग लिया था।

2011 पाब्लो पिकासो द्वारा बनाई गई न्यूड, ग्रीन लीव्स एंड बस्ट नाम की दुनिया में अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग लंदन की टेट गैलरी में प्रदर्शित की गई।

2012 एयरलाइन उड़ानें जीपीएस सिस्टम और पावर ग्रिड को सबसे बड़ी सौर भड़कना, पृथ्वी के पास से परेशान किया जाएगा, जो पांच साल में होता है, 6 मार्च 2012 को घटित होगा।

2013 प्रधान मंत्री रैला ओडिंगा, कलानोज़ो मुसियोका के चल रहे साथी ने दावा किया कि केन्या के राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाले गए थे।

मजबूर मेक्सिको और अमेरिका का खूनी इतिहास

अंशुमान तिवारी

डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया का कारोबारी भविष्य बदलने के लिए अमेरिकी बाजार में सामान बेचने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला तो बाद में किया, व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने 400 साल पुराना इतिहास बदलने का फरमान जारी किया। उन्होंने 16 लाख वर्ग किलोमीटर के मेक्सिको बेसिन यानी सेनो मेक्सिकाना यानी गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। यह समुद्री क्षेत्र अमेरिका के पांच राज्यों, छह मेक्सिकन राज्यों और क्यूबा को जोड़ता है। नाम बदलने से इतिहास और अतीत बदलने की झक राजनेताओं को अनोखा ही जीव बनाती है।

ट्रंप के चेहरे में लोगों को अचानक, 19वीं सदी के मध्य के राजनेता दिखने लगे, जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नाम पर अमेरिका का राज्य विस्तार करना चाहते थे। ट्रंप भी ग्रीनलैंड और कनाडा को लेकर कुछ न कुछ कहते रहे हैं। मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने के बाद मेक्सिको और अमेरिका का रक्तरंजित इतिहास फड़फड़ा उठा है, ट्रंप सिर्फ अमेरिका के पश्चिमी मुल्क का अतीत ही नहीं, बल्कि भविष्य भी बदलने (इंपोर्ट टैरिफ) को बख्तरबंद हैं, तो आइए टाइम मशीन भी तैयार है आपको ले जाने के लिए ऐसे युद्धोन्मादी दौर में, जहां अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने देश के पश्चिम का नक्शा बदल दिया था। मेक्सिको को लेकर ट्रंप की चिढ़ की जड़ शायद वहीं मिल जाए। हम उड़ चले हैं 1846 की तरफ, जब भारत में सर जॉन कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी। हम मेक्सिको की खाड़ी को पार करते हुए वेराक्रूज के ऊपर से मेक्सिको सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके नीचे जंग का मैदान है, जहां अमेरिका की फौज मेक्सिको सिटी पर लगभग कब्जा करने वाली है। वह आगे देख रहे हैं न एक पहाड़ी, उसका नाम है चापुलटपेक हिल। टाइम मशीन इस पहाड़ी से कुछ दूर जंगल में उतर रही है। यह सितंबर 1847 है, अमेरिका और मेक्सिको के युद्ध का निर्णायक क्षण आ गया है।

अमेरिकी जनरल विनफील्ड स्कॉट ने वेराक्रूज के जरिये समुद्री, थल और हवाई हमला किया है। यह अमेरिका-मेक्सिको युद्ध (1846-48) का सबसे ताकतवर हमला है। चुरुबुस्को में मेक्सिकन अमेरिकियों से भिड़ गए, मगर स्कॉट की फौज उन्हें रौंदते हुए मेक्सिको सिटी की तरफ बढ़ चली। उनका रास्ता रोका चापुलटपेक के किले ने। चापुलटपेक में एक बड़ा लोहमर्षक इतिहास बन रहा था। कल रात स्कॉट की सेना ने इस किले पर अभूतपूर्व गोला बारूद बरसाया। मेक्सिको सिटी पर अमेरिकी कब्जे के लिए यह किला ढहना जरूरी था। इस किले पर तैनात थे मेक्सिको के युवा सिपाही, जो अभी-अभी जंग में आए थे। इनमें छह कैडेट आखिरी तक जूझे और उनके रहने तक अमेरिकी फौजें किले के पास नहीं पहुंच पाईं, इनमें एक कैडेट थे जुआन एस्क्यूटिया। अंततः वह मेक्सिको का झंडा अपने शरीर से लपेटकर किले से कूद गए, ताकि अमेरिकी उसके मुल्क के ध्वज छू न सकें। मेक्सिको के निनो हीरोज (युवा सिपाही) की यह जंग दुनिया की उन तमाम लड़ाइयों में शुमार होगी, जो आजादी बचाने के लिए लड़ी गई हैं। मेक्सिको के लिए तो यह बलिदान का तीर्थ बन जाएगा। अब हम एक ऐसी अमेरिकी शख्सियत से मिलते हैं, जो अमेरिकी राज्य विस्तार की मुहिम में लगा था। हम 19वीं सदी की शुरुआत में हैं। जेम्स के पोल्क राष्ट्रपति हैं। पोल्क की राजनीति अमेरिका की सीमाएं बढ़ाने पर केंद्रित है। इसे उन्होंने 'मैनिफेस्ट डेस्टिनी' अभियान कहा है, यानी सेना के जरिये अमेरिकी पश्चिमी सीमाओं का विस्तार।

अब आप मेक्सिको और अमेरिका के पेचीदा रिश्तों की शुरुआत के गवाह बनेंगे, जो अगली कई सदियों तक इन दो पड़ोसियों को उलझाते रहेंगे। अमेरिका का मौजूदा नक्शा करीब से देखिए, जो आपकी सीट के सामने स्क्रीन पर आ रहा है। 21वीं सदी से आते हुए जो अमेरिकी नक्शा आपके जेहन में है, यह तो उससे अलग है। इसमें तो टेक्सास, कैलिफोर्निया और कई दूसरे राज्य नहीं दिख रहे। 1821 में जब मेक्सिको आजाद हुआ, तब ये राज्य उसका हिस्सा थे, अमेरिका के नहीं। राजधानी वाशिंगटन में चहलकदमी करते हुए आपको पता चलेगा कि मेक्सिको रिपब्लिक तो है, मगर राजनीति अस्थिर है। केंद्र बनाम राज्य का झगड़ा जारी है। व्हाइट हाउस के पास रहिएगा, क्योंकि वहां टेक्सास से एक खबर आने वाली है। टेक्सास में पुराने अमेरिकी?और मेक्सिको के बाशिंदे लड़ पड़े हैं। मामला है गुलामों का। मेक्सिको ने गुलामी का चलन बंद कर दिया है। पुराने अमेरिकियों को खेतों के लिए कामगार नहीं मिल रहे हैं।

यह 1845 का साल है। टेक्सास में बगावत की खबर व्हाइट हाउस आ गई। राष्ट्रपति जेम्स पोल्क को मैनिफेस्ट डेस्टिनी यानी अमेरिका के भौगोलिक विस्तार का मौका मिल गया है। ठीक सुना है आपने, व्हाइट हाउस ने टेक्सास को अमेरिका में मिला लिया। राष्ट्रपति के इशारे पर अमेरिकी सेना पश्चिम के मोर्चे पर पहुंच गई है। टेक्सास की सीमा पर झड़पें जारी हैं। मेक्सिको के पुराने नेता और सेनानायक एंतोनियो लोपेज डे सांता अन्ना लौट आए हैं और मेक्सिकन-अमेरिकी युद्ध के नगाड़े बज उठे हैं। टाइम मशीन चापुलटपेक हिल पर लौट आई, जहां हम उतरे थे। इस किले के ढहने के बाद मेक्सिको पर अमेरिकी कब्जा हो गया है। मेक्सिको तबाह होकर घुटनों पर आ गया है। राष्ट्रपति पोल्क की अमेरिका की सीमा बढ़ाओ मुहिम कामयाब रही है। मेक्सिको युद्ध बंद करने के लिए समझौते को तैयार है। टाइम मशीन अब टेक्सास के गुआदालूपे हिडाल्गो शहर में है। यह 1848 है। मेक्सिको मजबूर है, उसने कैलिफोर्निया, नेवादा, टेक्सास, उटा, एरिजोना और कोलोराडो?और वायोमिंग के हिस्से अमेरिका को दे दिए हैं। करीब-करीब आधा मेक्सिको अब अमेरिका का है। अमेरिका अगले एक दशक में मेक्सिको से कुछ और हिस्सा भी खरीदेगा और सीमा को संतुलित करेगा। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि जीत के बाद अमेरिका ने पूरे मेक्सिको को ही क्यों नहीं मिला लिया... कहते हैं कि गुलामों को लेकर अमेरिकी राजनीति में तत्कालीन विभाजन इसकी वजह था। यह संधि होने तक अमेरिकी कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नए राज्यों में गुलामों की व्यवस्था बनाए रखनी है या फिर खत्म करनी है। इसलिए मेक्सिको के आधे हिस्से को मिलाने का फैसला किया गया। तो क्या अमेरिकी नेताओं की नई पीढ़ी गुआदालूपे की संधि से इन्कार कर रही है, गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलने के बाद ट्रंप क्या करना चाहते हैं? बहुत से लोगों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में जेम्स पोल्क दिख रहे हैं। मेक्सिको पर हमलावर ट्रंप साजिश कथाओं को जन्म दे रहे हैं। यह मार्च, 2025 है। हम वाशिंगटन आ गए हैं।

तमिलनाडु में हिंदी के पक्ष में उठती आवाजें

उमेश चतुर्वेदी

भाषाएं उन लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दा होती हैं, जो उन्हें प्राथमिक जुबान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसी भावना का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब हिंदी के समर्थन में तमिलनाडु के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। श्रीधर वेंबु तमिल माटी के ही सपूत हैं। इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और कारोबार की दुनिया में उनकी कंपनी जोहो का डंका बज रहा है। यही श्रीधर वेंबु खुले तौर पर कहने लगे हैं कि आइए, हम हिंदी सीखें। हिंदी न जानने की वजह से हो रही कारोबारी दुश्वारियों को वे समझ रहे हैं, इसीलिए वह न सिर्फ हिंदी सीख रहे हैं, बल्कि इसकी मुनादी भी कर रहे हैं। श्रीधर ने एक्स पर जब हिंदी सीखने की अपील की, तो इसे स्टालिन की भाषाई राजनीति के जवाब के तौर पर देखा जाने लगा। ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि तमिल संस्कृति और भाषा के सम्मान के नाम पर वह तमिल भावनाओं को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में वह कभी हिंदी को साम्राज्यवादी बताते हैं और जब यह आरोप साबित नहीं हो पाता, तो हिंदी पर यह आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हटते कि अपने हृदय प्रदेश की बोलियों और छोटी भाषाओं को उसने निगल लिया है। हकीकत यह है कि हिंदी ने अपने हृदय प्रदेश की किसी भी भाषा के अस्तित्व को कोई चोट नहीं पहुंचायी है। उलटे वह इनके बीच संपर्क भाषा के रूप में काम कर रही है। अवधी, भोजपुरी, बैसवाड़ी या ब्रजभाषी जब अपने भाषा समुदाय से दूर के लोगों से मिलते हैं, तब उनके सहज संवाद की भाषा हिंदी होती है। इस प्रक्रिया में वह हर भाषा से कुछ शब्द लेती है, खुद भी समृद्ध होती है और अपनी बोली या उपभाषाओं को भी ताकतवर बनाती है। महात्मा गांधी ने तमिल और तेलगु युवाओं से 107 साल पहले हिंदी सीखने की अपील की थी। उनके ही आह्वान पर 1918 में एनी बेसेंट और रामास्वामी अय्यर ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। गांधी जी का सपना था कि तमिल और तेलुगू जैसे अहिंदीभाषी इलाकों के लोग हिंदी तो सीखें ही, हिंदी को लेकर अपने राज्यों में माहौल भी बनायें। गांधी जी का वह सपना आज सच होता नजर आ रहा है। श्रीधर वेंबु जैसे घोर तमिलभाषी का हिंदी के समर्थन में सामने आना और उनके साथ तमिलनाडु ही नहीं, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना आदि के लोगों का खड़ा होना मामूली बात नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे आर्थिक विचारक एस गुरुमूर्ति तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक हलके की महत्वपूर्ण आवाज हैं। लेकिन हिंदी को लेकर तमिलनाडु में जो सामान्य धारणा रही है, उसकी वजह से हिंदी समर्थक उनके सुर को तमिल माटी में तवज्जो देने से बचा जाता रहा है। पर श्रीधर वेंबु की आवाज और उनके समर्थन में सोशल मीडिया मंचों पर उमड़े युवा स्वरों ने गुरुमूर्ति की हिंदी समर्थक आवाज को ताकत दी है। हिंदी का समर्थन करते हुए श्रीधर यह भी कह रहे हैं कि उनकी कंपनी का कामकाज तमिलनाडु की तुलना में दूसरे राज्यों में ज्यादा है, जहां उनकी कंपनी अपने तमिल अधिकारियों और प्रोफेशनल को भेजने में हिचकती है, क्योंकि वे दूसरे राज्यों में सहज संवाद विशेषकर जमीनी स्तर पर नहीं कर पाते। वर्ष 1965 में तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ था, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के चलते हिंदी को राजकाज की भाषा का स्थान लेने के लिए 15 साल की अवधि 25 जनवरी, 1965 को पूरी हो रही थी। तब क्षेत्रीय द्रविड़ राजनीति को हिंदी विरोध में अपनी राजनीतिक राह दिखी। तमिल उपराष्ट्रीयता को उन्होंने हिंदी विरोध के नाम पर उभारा और स्थानीय लोक को अपने पक्ष में लामबंद किया। इस कारण केंद्र सरकार को हिंदी को राजकाज की भाषा बनाने के संवैधानिक आग्रह को अनंत काल के लिए पर टालना पड़ा। इस अर्थ में तमिलनाडु का हिंदी विरोधी आंदोलन सफल कहा जाएगा। तभी से तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू नहीं है। पर सीबीएसइ बोर्ड वाले विद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। अखिल भारतीय नौकरियों के मद्देनजर स्थानीय लोग अपने बच्चों को सीबीएसइ बोर्ड वाले स्कूलों में पढ़ा तो ही रहे हैं, उन्हें अलग से हिंदी की कोचिंग भी दिला रहे हैं। तमिलनाडु की प्रौढ़ हो चुकी पीढ़ी में एक वर्ग ऐसा भी है, जो सोचता है कि हिंदी विरोधी आंदोलन में हिस्सा लेकर उसने गलती की। यह गलती सुधारने के लिए वह पीढ़ी अपने बच्चों को हिंदी से घृणा करना सिखाने से बचती है। इसके अलावा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा अब तक 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को हिंदी सिखा-पढ़ा चुकी है। अब तमिलनाडु में ऐसे लोग मिल जायेंगे, जो हिंदी के समर्थन में आवाज उठाते हैं।

कुंभ समाप्त, अब चार धाम यात्रा की तैयारी कीजिए

अशोक मधुप

कुंभ यात्रा लगभाग बीत गई। इसके बाद 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। श्रद्धालुओं का जो काफिला कुंभ में दिखाई दिया, ऐसा ही कमोबेश चार धाम यात्रा में नजर आने की आशा है। कुंभ के सफल आयोजन की जिम्मेदारी जहां उत्तर प्रदेश सरकार और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी। ऐसी ही जिम्मेदारी चार धाम यात्रा में उत्तरांचल की सरकार और यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होगी। पुष्कर सिंह धामी इस श्रद्धालुओं के रेले को किस तरह नियंत्रित करते हैं। इस यात्रा की किस तरह तैयारी करते है। इसकी योग्यता उन्हें प्रदर्शित करने का अवसर आ रहा है। हालाकि उत्तरांचल में भाजपा की सरकार है। केंद्र उन्हें इस आयोजन में पूरी मदद करेगा, हर संभव मदद करेगा, किंतु श्रद्धालुओं के रेले को तो उत्तरांचल सरकार को ही संभालना होगा। 26 फरवरी को महाकुंभ का अंतिम स्नान था। शिवरात्रि तक 66 करोड 21 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके। अभी ये चलेगा। एक तरह से फरवरी के बाद भी कुछ समय ये चलेगा। आयोजन की समाप्ति तक एक अनुमान के अनुसार कुंभ स्नान करने वालों की संख्या 70 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी।

देश में दशकों के बाद सनातन ने करवट ली है। वह अपने आस्था स्थलों की ओर बेतहाशा दौड़ रहा है। राम मंदिर के निर्मित होते ही सनातन का ऐसा उदय हुआ जैसा कभी 1000 वर्ष पहले हुआ करता होगा। कुंभ आने का प्रचार पहली बार भारत से बाहर निकल दुनिया के तमाम देशों के टीवी चैनल्स तक पंहुच गया। अनेक देशों की सरकारों को निमंत्रण पत्र देने भारत के राजदूत गए। परिणाम स्वरूप, 60 करोड 21 लाख श्रद्धालु शिवरात्रि तक कुंभ स्नान चुके हैं। काशीङ्कअयोध्या-चित्रकूट में जगह खाली नहीं थी। लोगों का जिस तरह प्रयागराज जाना लगातार चल रहा है उसे देखते हुए साफ हो जाता है कि कुंभ

समापन तक 70 करोड़ श्रद्धालु संगम की डुबकी लगा चुके होंगे। इस रिकॉर्ड की मिसाल पूरी दुनिया में कभी नहीं मिलेगी।

ये महाकुंभ मार्च के प्रारंभ में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगी चारधाम यात्रा।चार धाम यात्रा के दो धाम यमुनोत्री और गंगोत्री के पवित्र द्वार तीर्थयात्रियों के लिए अक्षय तृतीया के पवित्र दिन अर्थात 30 अप्रेल को खुलेंगे। यमुनोत्री और गंगोत्री के खुलने के कुछ ही दिनों बाद, मई के तीसरे या चौथे सप्ताह से अन्य दो मंदिर, केदारनाथ और बद्रीनाथ तीर्थयात्रियों से भर जाएँगे। जबकि, श्रद्धालु विजय दशमी के शुभ दिन बद्रीनाथ धाम को विदा करते हैं, उसके बाद दीपों के त्योहार दिवाली पर गंगोत्री धाम को बंद कर दिया जाता है और केदारनाथ और यमुनोत्री धाम एक साथ यम द्वितीया/भाई दूज पर बंद कर दिए जाते हैं।

चूंकि चारधाम यात्रा घड़ी की सुई की दिशा में चलती है, इसलिए पवित्र यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है। उसके बाद क्रमशः गंगोत्री और केदारनाथ से गुजरते हुए चार धाम की पवित्र यात्रा बद्रीनाथ पंहुचती है।

इसमें को शक नहीं कि कुंभ यात्रियों का ये रेला, सनातन धर्म के श्रद्धालु दो माह मार्च और अप्रैल आराम करके अब चार धाम यात्रा की ओर निकलेंगे। उत्तराखंड वासियों के लिए अतिथि भगवान होता है लेकिन यहां ये कुम्भ जैसी भीड़ आई को कैसे संभालेगा, ये समय बताएगा। ये उत्तरांचल के बडी चुनौती होगा। श्रद्धालुओं को मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। आज भी गर्मी के मौसम में कुछ साल से पहाड़ पूरी तरह पैक हो जाते हैं। लोगों को यहां न होटल में जगह मिलती है, न वाहन पार्किंग को स्थान। यहां का भूगोल, मौसम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कई मोर्चे पर चुनौती पेश करती है। 2013 की केदारनाथ की दारुण आपदा को दुनिया देख-सुन चुकी हैं। इस बार उत्तराखंड सरकार और शासन को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। चारधाम की यात्रा सबके लिए सुरक्षित और सुखद रहे,ये सरकार की जिम्मेदारी और भीड़ प्रबंधन पर निर्भर करता है।

राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से शुरू हुआ कुंभ से उपजा सनातन का जोश और आस्था आजकल हिंदू समाज में हिलोरे ले रही है। कुंभ यात्रा के बावजूद इस बार शिवरात्रि पर कांवड़ियों की संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ ज्यादा ही रहे। कावंड लाने वालों में इस बार महिलाएं और युवती भी ज्यादा नजर आईं। कांवड़ सेवा शिविर भी पहले से काफी ज्यादा नजर आए। कांवड यात्रा के प्रत्येक सौ कदम पर अबकि बार शिविर लगे थे। उनमें स्त्री-पुरूष मिलकर सेवा कर रहे थे। कांवड यात्रा के मार्ग पर लोग कारों में फल और बिसलरी की पानी की बोलते भरे खड़े थे। वे आने वाले कांवड़ियों को फल और पानी की बोतल बांट रहे थे। लेखक का जनपद हरिद्वार से सटा है। यहां डाक कांवड़ और कलश की बंहगी में जल लाने का प्रचलन नही है, किंतु इस बार डाक कांवड काफी संख्या में दिखाई दी। कुंभ यात्रा और कावंड यात्रा का यह सनातन का रेला आने वाली चार धाम यात्रा में भी दीखने की पूरी उम्मीद है।

उत्तरांचल सरकार को देखना है कि वह आने वाले चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं को कैसे संभालती है। अभी उसके पास यात्रा की तैयारी के लिए दो माह का समय है। मेरठ-पौड़ी नेशनल हाई-वे को फोर लेन करने का काम जारी है। उम्मीद है कि यात्रा की शुरूआत हरिद्वार और ऋषिकेश से कर उसकी वापसी पौड़ी मार्ग से होगी। ऐसा है तो उसे इस मार्ग का तैयार कराने के लिए केंद्र को अभी से दबाव देना होगा। राम मंदिर पारण प्रतिष्ठा के बाद देशवासी जिस तरह अपने तीर्थों की ओर दौड़ रहे हैं, उम्मीद है ऐसे ही श्रद्धालु चार धाम यात्रा में उमड़ेंगे। वे चार धाम यात्रा के लिए सरकारी साधन बस, ट्रेन और विमानों से आएंगे तो भारी तादाद में श्रद्धालु अपने वाहन और टैक्सियों से आएंगे। इन वाहनों कार, टैक्सियों और बसों को उत्तरांचल कैसे संभालेगा, उसे देखना है। प्रयागराज से तो इसलिए सब कुछ हो गया कि वहां आयोजन प्लेन में था। उत्तरांचल में तो सब कुछ पहाड़ों में है। वहां तो पार्किंग भी प्राय सड़क किनारे ही होती है। इस सब का प्रबंधं कैसे हो, इसकी व्यवस्था अभी से बनानी होगी।

दरअसल पिछले कुछ सालों देश में संपन्नता बढ़ी है। अब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के युवक रविवार और शनिवार का अवकाश देख शुक्रवार की शाम पिकनिक के लिए पहाड़ की ओर निकल जाते हैं। इसलिए पिछले कुछ साल में इन अवकाश के दिनों विशेषकर गर्मियों के मौसम में उत्तरांचल के होटल पूरी तरह भरे होतें हैं। सड़कों पर वाहनों का रेला होता है। पहाडों के होटल भरे होने और सड़कें पर जाम की खबर अखबारों की सुर्खियां बनती रहती हैं। ये ही गर्मी का मौसम चार धाम यात्रा का है। ऐसे में उत्तरांचल सरकार को प्रयास करना होगा कि ये सैलानी चार धाम यात्रा के स्थल गढ़वाल न आए। उन्हें कुमायूं और अन्य पर्वतीय प्रदेशों की ओर भेजना होगा। इसके लिए अभी से प्रचार करना होगा। जनता को जागरूक करना होगा और माहौल बनाना होगा।

अभी चार धाम यात्रा में दो माह का समय है। इसी समय में उत्तरांचल सरकार को तैयारी करनी है। भीड़ नियंत्रण का प्लान बनाना है। यात्रा के श्रद्धालु और उनके वाहन के पार्किंग की अभी से प्लानिंग करनी होगी। ये दो माह उसके लिए युद्धस्तर पर कार्य करने और व्यवस्था बनाने के लिए हैं। कुंभ यात्री के दौरान दिल्ली में हुए हादसे से रेलवे को सीख लेनी होगी। उसे भी बड़ी प्लानिंग करनी होगी।

मोटापे से जाता है देश में भुखमरी-कुपोषण को रोकने का रास्ता

योगेंद्र योगी

भारत विडम्बनाओं से भरा देश है। इन्हीं में से एक है मोटापा और भुखमरी। इनमें एक जुड़ाव भी है। एक तरफ अनावश्यक और अत्यधिक खाने से बढने वाला मोटापे से होने वाली बीमारियां राष्ट्रव्यापी समस्या बनती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आबादी का एक बड़े हिस्सा दो वक्त का भरपेट भोजन नसीब नहीं होने से कुपोषित होकर रोगग्रस्त हो रहा है। यदि मोटापा खत्म या नियंत्रित हो जाए तो इससे भुखमरी व कुपोषण के लिए धन की कमी पूरी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 119वी श्रृंखला में देश में बढ़ती मोटापे की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मोटापे के मामले दोगुने हो गए हैं और भारत में मोटापे की व्यापकता पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर छोटे-छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका है कि खाने के तेल में 10 पर्सेंट की कमी करना। भोजन में खाद्य तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के दस प्रसिद्ध लोगों को नॉमिनेट किया। मोटापा सिर्फ सेहत का मसला नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है। एक नई स्टडी के अनुसार, भारत में मोटापे का आर्थिक बोझ 2030 तक बढ़कर 6.7 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा। यह लगभग 4,700 रुपये प्रति व्यक्ति होगा, जोकि जीडीपी का 1.57 फीसदी है।

ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्जर्वेटरी के अनुसार, 2019 में मोटापे का आर्थिक प्रभाव 2.4 लाख करोड़ रुपये था। यह लगभग 1,800 रुपये प्रति व्यक्ति और जीडीपी का 1.02 फीसदी था। 2060 तक यह आंकड़ा बढ़कर 69.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जो प्रति व्यक्ति 44,200 रुपये और जीडीपी का 2.5 फीसदी होगा। यह स्टडी बताती है कि मोटापा सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा है।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार, पुरुषों और महिलाओं में क्रमशः 44 प्रतिशत और 41 प्रतिशत लोग अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। पिछले सर्वेक्षण में यह आंकड़ा क्रमशः 37.7 फीसदी और 36 फीसदी था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। विश्व मोटापा महासंघ ने कहा कि भारत में दुनिया में मोटे व्यक्तियों का तीसरा सबसे बड़ा प्रतिशत है। किसी व्यक्ति को तब मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है जब उसका बीएमआई 27.5 से अधिक हो। पिछले 10 वर्षों में, भारत की मोटापे की दर लगभग तीन गुनी हो गई है, जिसका असर देश की शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी पर पड़ रहा है। मोटापे का वैश्विक संकट सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोटापे की दर अधिक है, जो देश के तेज़ आर्थिक विस्तार और बदलती जीवन शैली मानकों के साथ मेल खाता है। भारत में 100 मिलियन से अधिक लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। भारत में 12 प्रतिशत पुरुष और 40 प्रतिशत महिलाएं पेट के मोटापे से ग्रस्त हैं। केरल (65.4 प्रतिशत), तमिलनाडु (57.9 प्रतिशत), पंजाब (62.5 प्रतिशत) और दिल्ली (59 प्रतिशत) में यह दर बहुत ज़्यादा है।

मध्य प्रदेश (24.9 प्रतिशत) और झारखंड (23.9 प्रतिशत) में यह दर कम है। आंकड़ों के अनुसार, भारत में पहले से ही 14.4 मिलियन बच्चे मोटे हैं। भारत में बचपन में मोटापे के प्राथमिक कारणों में खराब आहार विकल्प, निष्क्रियता और एक गतिहीन जीवन शैली शामिल है। प्रोसेस्ड स्नैक्स और फास्ट फूड की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बच्चे उच्च कैलोरी, कम पोषक तत्व वाले आहार खा रहे हैं, जिससे वजन बढ़ता है और मोटापा होता है। बचपन में मोटापे के परिणाम व्यापक हैं और लंबे समय में बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मोटे बच्चों को टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और सांस लेने में कठिनाई जैसी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं होने का उच्च जोखिम होता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें निराशा और खराब आत्मसम्मान सहित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव होने की अधिक संभावना है, जो उनके सामान्य स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। विडम्बना यह है कि देश मोटापे से होने वाली चुनौतियों से जूझ रहा है, वहीं कुपोषण की समस्या से भी जूझ रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में 127 देशों में भारत का स्थान 105वां है। हालांकि पिछले सालों की तुलना में इस साल भारत की रैंक में सुधार हुआ है। लेकिन भारत अभी भी गंभीर भूख की समस्याओं वाले देशों में शामिल है। 2024 की रिपोर्ट में भारत का स्कोर 27.3 है जो भुखमरी के एक गंभीर स्तर को दर्शाता है।

रिपोर्ट में हाल के वर्षों में भारत में कुपोषण के प्रसार में मामूली वृद्धि का उल्लेख किया गया है। भारत की रैंकिंग अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से पीछे हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से केवल ऊपर है। श्रीलंका 56, नेपाल 68 और बांग्लादेश 84वें स्थान पर भारत से काफी आगे हैं। भारत में कुपोषण की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। यहां बहुतों को तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता और जिनको मिल भी रहा है उनके भोजन में पोषण की भारी कमी है। इसका खामियाजा नन्हें बच्चों को उठाना पड़ रहा है। भारत को अभी भी बाल कुपोषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें विश्व स्तर पर बच्चों में दुबलापन (18.7 प्रतिशत) सबसे अधिक है।

यूनुस के नेतृत्व से निराश हैं बांग्लादेश के सेना प्रमुख

सुबीर भौमिक

बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां ने हाल ही में एक प्रमुख संपादक से कहा कि वह देश में तेजी से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की 'विफलता' से निराश हैं। उन्होंने कथित तौर पर इस बात पर 'गंभीर संदेह' जताया कि क्या यूनुस प्रशासन वास्तव में निकट भविष्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकता है। जनरल वकार एक रूढ़िवादी और सुरक्षित ढंग से चलने वाले सैन्य नेता हैं, जिन्होंने पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के हटने के बाद देश में मार्शल लॉ लागू करके सीधे नियंत्रण लेने के सैन्य एवं बाहरी, दोनों उकसावे का विरोध किया। उन्होंने अपने कुछ करीबी दोस्तों से जो कहा, उनमें से कुछ ने इस लेखक को बताया कि बांग्लादेश में सैन्य शासन कभी भी लोकप्रिय नहीं रहा है और जियाउर रहमान और एचएम इरशाद जैसे जनरलों को शीघ्र ही जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी। यहां तक कि तत्कालीन सेना प्रमुख मोईन यू अहमद के नेतृत्व में सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार (2006-08) भी नए चुनावों की मांग बढ़ने के कारण अलोकप्रिय हो गई। इसलिए यह जानते हुए कि प्रत्यक्ष सैन्य शासन दुनिया भर में तेजी से अलोकप्रिय हो रहा है, वकार ने सेना को सीधे प्रभार संभालने से दूर रखने का फैसला किया। उनके करीबी लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, सैन्य प्रमुख जल्द से जल्द चुनाव कराने के इच्छुक हैं और उसके बाद निर्वाचित सरकार को कार्यभार संभालने देना चाहते हैं। अंतरिम सरकार जितनी लंबी चलेगी और कानून-व्यवस्था के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में विफल रहेगी, सेना को ही दोषी ठहराया जाएगा। जब छात्रों और कट्टरपंथियों की उग्र भीड़ ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर में स्थित संग्रहालय को ध्वस्त किया, तो सैनिकों के मूकदर्शक बने रहने से सेना की छवि खराब ही हुई। पिछले साल जुलाई-अगस्त में जनरल वकार द्वारा आंदोलनरत छात्रों पर गोली न चलाने और खून-खराबा न करने के फैसले का पूरे मुल्क में स्वागत किया गया था। लेकिन, हर तरफ फैली अराजकता के बीच मूकदर्शक सेना की छवि उन लोगों को रास नहीं आ रही है, जो स्थिरता और सुरक्षा चाहते हैं। कुछ लोग पहले से ही सवाल उठा रहे हैं कि मुल्क में कानून-व्यवस्था बहाल करने में असमर्थ सेना को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। सेना प्रमुख जनरल वकार को यह एहसास होने लगा है कि उन्हें सिर्फ वादे करने के बजाय निर्णायक रूप से काम करना होगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरल वकार ने ही हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद राजनीतिक दलों, सिविल सोसायटी और छात्र आंदोलनकारियों से विचार-विमर्श के बाद अंतरिम सरकार स्थापित करने की पहल की थी। सेना प्रमुख ने हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में कहा कि वे सामान्य स्थिति बहाल करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं और उन्होंने जल्द से जल्द राजनीतिक व्यवस्था बहाल करने का भी वादा किया। हालांकि, सेना प्रमुख ने अब तक यूनुस और उनकी सरकार का दृढ़ता से समर्थन किया है, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि नोबेल पुरस्कार विजेता को समय से पहले चुनाव कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह पहले सुधारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वह असहज होने लगे। यह बेचैनी तब सामने आई, जब जनरल वकार ने एकतरफा तौर पर कहा कि चुनाव 2025 में ही होंगे, जबकि उस समय यूनुस अमेरिका में थे।

इन आदतों से करें अपने दिन की शुरुआत बॉडी से लेकर माइंड तक सब रहेगा हेल्दी

कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से हो तो पूरा दिन काफी बढ़िया से गुजरता है। आपने भी इसको महसूस किया होगा कि अगर आपके दिन की शुरुआत आलस भरा होता है तो पूरा दिन ही आलस जैसा गुजरता है। कई बार खराब आदतों के कारण ऐसा होता है। ऐसे में आप भी अपने दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप इन पांच आदतों को अपने दैनिक जीवन में फॉलो कर सकते हैं।

सुबह-सुबह जल्दी उठें

अगर आप भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल और स्वस्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठने के बाद वॉक पर जा सकते हैं। इसके बाद आप धूप भी ले सकते हैं। इससे आपकी बॉडी हेल्दी बनेगी और शरीर में विटामिन डी की कमी भी नहीं होगी। धूप हड्डियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है।

गुनगुना पानी पीने की डालें आदत

आप सुबह-सुबह गुनगुना पानी पी सकते हैं। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को कम करता है। सुबह-सुबह गुनगुना पानी पीने से पाचन भी बेहतर होती है। आप गुनगुने पानी के साथ नींबू को भी मिला सकते हैं।

मेडिटेशन और योग से करें दिन की शुरुआत

आप अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन और योग से भी कर सकते हैं। यह दिमाग को शांत करेगा, जिससे आप पूरे दिन अपने काम को समय से कर पाएंगे। मेडिटेशन और योगा करने से स्ट्रेस कम होता है और पूरे दिन बॉडी में एनर्जी बनी रहती है।

हेल्दी ब्रेकफास्ट से माइंड रहेगा एक्टिव

सुबह के समय हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना काफी अहम होता है। यह शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ दिमाग को भी काफी एक्टिव करता है। आप अपने सुबह के नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स जैसे चीजों को शामिल कर सकते हैं।

पूरे दिन की करें प्लानिंग

पूरे दिन फोकस्ड रहने के लिए आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग सुबह के समय में ही कर लें। इसके बाद आप एक-एक काम को पूरा करें। इससे आप स्ट्रेस और बर्डन फ्री रहेंगे।

डायबिटीज और गठिया रोगी आज से ही शुरू कर दें ये आसान सा काम, मिलेंगे फायदे

हम में से ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय या कॉफी के साथ होती है, पर क्या जो चाय हम सुबह-सुबह पीते हैं उससे सेहत को लाभ होता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल बना रहता है तो बिना देर किए आपको चाय के उन विकल्पों की तरफ स्विच करना चाहिए जिससे सेहत को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अब सवाल उठता है कि फिर कौन सी चाय पिएं?

आहार विशेषज्ञ कहते हैं, दूध और चीनी वाली पारंपरिक चाय की जगह अगर आप हर्बल टी पीने की आदत बनाते हैं तो ये कहीं अधिक लाभकारी हो सकता है। ग्रीन-टी हो या अदरक और हल्दी वाली चाय ये सभी औषधीय गुणों से भरपूर होती है जिससे सेहत को कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं।

कई अध्ययनों में सहजन की पत्तियों से तैयार चाय पीने को भी बहुत फायदेमंद बताया गया है।

तमाम गुणों से भरपूर है सहजन

सहजन को आयुर्वेद में एक चमत्कारी औषधि के रूप में जाना जाता है। इसके पत्तों, फूलों, फलों और छाल का उपयोग कई स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने से लेकर ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने, सूजन को कम करने और हड्डियों को स्वस्थ रखने तक में सहजन अपने विशेष स्वास्थ्य प्रभावों के लिए जाना जाता है।

इसमें आवश्यक विटामिन ए, सी, के और बी कॉम्प्लेक्स और आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिज होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को नियमित रूप से जरूरत होती है। सहजन की पत्तियों से बनी चाय का सेवन आपको कई बीमारियों से बचाए रखने में भी मददगार हो सकती है।

क्या कहती हैं आहार विशेषज्ञ?

इस चाय के लिए एक गिलास पानी में सहजन की 5-6 पत्तिया डालकर 10 मिनट तक उबालें। इसमें शहद और नींबू भी मिलाकर पिया जा सकता है।

आहार विशेषज्ञ पायल शर्मा कहती हैं, सहजन की चाय का सुबह खाली पेट सेवन करना फायदेमंद रहता है, लेकिन इसके अधिक सेवन से पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, इसलिए अगर आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं तो इसका सेवन न करें। अगर आपको पहले से कोई क्रोनिक बीमारी है तो भी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन किया जाना चाहिए।

डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद

आहार विशेषज्ञ बताते हैं, सहजन की चाय में एंटीडायबिटिक गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये इन्सुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर शरीर में शुगर की मात्रा को संतुलित करने में सहायक है। सहजन की पत्तियों में विटामिन सी, एंटीऑक्सिडेंट और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करता है।

डायबिटीज रोगियों में इम्युनिटी की समस्या अधिक देखी जाती है, ऐसे में ये चाय मधुमेह के शिकार लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है।

आर्थराइटिस में भी मिलता है आराम

सहजन में शरीर को डिटॉक्स करने वाले गुण पाए जाते हैं, जो शरीर से गंदगी को बाहर करके पेट की समस्याओं, जैसे- कब्ज, अपच और एसिडिटी को दूर करते हैं। इस चाय से पाचन तंत्र भी मजबूत बनता है। सहजन की पत्तियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाकर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव करते हैं।

कहीं आप भी तो नहीं कर रहे एकतरफा प्यार? इन संकेतों से कर लें पहचान

हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान हो जो उससे खूब प्यार करें। हालांकि, हर कोई इतना लकी कहां होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, जो किसी से प्यार तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता है कि उनका प्यार एकतरफा है या फिर दो-तरफा।

क्या आप भी करते हैं एकतरफा प्यार ?

एकतरफा प्यार काफी तकलीफों से भरा होता है। इसमें सामने वाले व्यक्ति से प्यार नहीं मिलता है। अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका प्यार एकतरफा है या फिर दो तरफा तो हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं, जिससे आप आसानी से इस बारे में पता कर सकते हैं।

एकतरफा प्यार का पता कैसे लगाएं?

अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं और आप ही हर बार किसी भी चीज को लेकर पहल करते हैं, यहां तक की बातचीत करने की भी तो यह एकतरफा प्यार का संकेत हो सकता है। आप जिससे भी प्यार करते हैं और उनसे मिलने की इच्छा जताते हैं और सामने वाला व्यक्ति इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है तो आपका प्यार एकतरफा हो सकता है।

क्या आप जिससे प्यार करते हैं वह आपके बातों को गौर से सुनता है? अगर इसका जवाब नहीं है तो आपका प्यार दो तरफा न होकर एकतरफा हो सकता है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके बातों को हर बार नजरअंदाज कर रहा है और हर बार आपको दरकिनार कर रहा है तो आपका प्यार एकतरफा हो सकता है।

आप जिससे प्यार करते हैं और कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं और सामने वाला व्यक्ति सीधे मना कर देता है या फिर बार-बार बहाना बनाता है तो इससे साफ पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति आप में इंट्रेस्टेड नहीं है। यह भी एकतरफा प्यार का संकेत हो सकता है।

एकतरफा प्यार से कैसे निपटें?

अगर आपके भी लग रहा है कि आप जिससे भी प्यार करते हैं वह सिर्फ एकतरफा प्यार है तो यह काफी तकलीफदेह होता है। ऐसे में आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इससे निपटने के लिए आप सबसे पहले अपने से प्यार करना सीखें और फिर किसी बेहतर साथी की तलाश करें।

महिला दिवस पर ऑफिस में पहनकर जाएं खास तरह के गुलाबी आउटफिट

महिला दिवस एक खास मौका होता है, जब महिलाएं अपने व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को सेलिब्रेट कर सकती हैं। इस दिन को और भी खास बनाने के लिए आप गुलाबी (पिंक) रंग के आउटफिट्स को अपने ऑफिस लुक में शामिल कर सकती हैं।

गुलाबी रंग फेमिनिनिटी, ग्रेस और पॉजिटिविटी को दर्शाता है। ऐसे में इस महिला दिवस पर गुलाबी रंग के आउटफिट्स न केवल आपकी स्टाइल स्टेटमेंट को बेहतर बनाएंगे, बल्कि यह दिन को और भी खास बना देंगे। तो इस बार ऑफिस में अपने पिंक पावर लुक के साथ आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं और इस दिन को पूरे स्टाइल में सेलिब्रेट करें।

पेस्टल पिंक फॉर्मल सूट

दफ्तर में ज्यादातर महिलाएं सूट कैरी करना पसंद करती हैं। ऐसे में अगर आप भी ऑफिस में एक स्मार्ट और प्रोफेशनल लुक चाहती हैं, तो पेस्टल पिंक ब्लेजर के साथ मैचिंग ट्राउजर या स्कर्ट पहनें। इसे व्हाइट टॉप और न्यूड हील्स के साथ पेयर करें।

पिंक इंडो-वेस्टर्न

अगर आप इंडो-वेस्टर्न लुक चाहती हैं, तो पिंक रंग का इंडो-वेस्टर्न आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। इसे सिल्वर ज्वेलरी और सफेद जूती के साथ स्टाइल करें। ये लुक कम्फर्टेबल होने के साथ-साथ ऑफिस-फ्रेंडली भी रहेगा।

पिंक शर्ट और ट्राउजर

यदि आपको फॉर्मल लुक पसंद है तो ऑफिस के लिए लाइट पिंक शर्ट को व्हाइट या बेज ट्राउजर के साथ कैरी करें। ये एक मिनिमलिस्ट और क्लासी लुक देगा। इसके साथ पैरों में पंप्स या लोफर्स परफेक्ट रहेंगे।

पिंक मिडी ड्रेस

अगर आपके ऑफिस में सेमी-फॉर्मल ड्रेस कोड है, तो एक सॉफ्ट पिंक मिडी ड्रेस बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसे बेल्ट और स्टाइलिश ब्लॉक हील्स के साथ पेयर करें। ये आपको स्मार्ट और ग्रेसफुल लुक देगा।

मार्च के महीने में लगाएं गंधराज फूल वाला पौधा, पूरे गर्मी आएगा फूल

मार्च का महीना बागवानी के लिए सबसे बेहतर होता है। इस समय मौसम बसंत के साथ काफी सुहाना होता है। मार्च के महीने में पौधे आसानी से लग जाते हैं और इनकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है। वहीं, मार्च के महीने से ही गर्मी की हल्की-हल्की शुरुआत हो जाती है।

सुगंधित फूल वाला पौधा है गंधराज

अगर आप भी अपने घर में किसी ऐसे फूल के पौधे को लगाने के बारे में सोच रहे हैं, जिसका फूल पूरे गर्मी आए तो आप गंधराज के पौधे पर विचार कर सकते हैं। यह सुगंधित फूल वाला पौधा इस मौसम में आसानी से उग जाएगा और इसको लगाना काफी आसान भी होता है। एक बार लग जाने के बाद इसको अधिक केयर करने की जरूरत नहीं होती है।

गंधराज का पौधा कैसे लगाएं?

गंधराज के पौधे को सुगंधित फूलों और शानदार खुशबू के लिए जाना जाता है। इसको आप 10 से 12 इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं। वहीं, इसकी मिट्टी को बनाने के लिए आप इसमें कोकोपीट, रेत और गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं। गंध राज के पौधे को अधिक धूप की जरूरत नहीं होती है। दिन में आप कम से कम तीन से चार घंटा धूप में इसको रख सकते हैं।

गंधराज के पौधे की देखभाल कैसे करें?

गंधराज के पौधे की देखभाल करना काफी आसान होता है। हालांकि, कई बार गंधराज के पौधों में फंगस और कीड़े लग जाते हैं, जिसको हटाना काफी जरूरी होता है। इसको हटाने के लिए आप नीम तेल या साबुन पानी का स्प्रे कर सकते हैं। अगर इसकी पत्तियां पीली होने लगे तो आप इसकी मिट्टी में खाद जरूर डालें।

जेब खाली, बैंक बैलेंस जीरो? इन आदतों को अभी बदलें और ऐसे शुरू करें सेविंग

क्या आपका बैंक बैलेंस हर महीने खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है? क्या आप बचत करना चाहते हैं, लेकिन हर बार नाकाम रहते हैं? अगर हां, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि आपकी कुछ रोजमर्रा की आदतें ही इस परेशानी की जड़ हों। अच्छी खबर यह है कि इन आदतों में थोड़ा सा बदलाव करके आप आसानी से अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। तो क्यों न आज ही सही दिशा में पहला कदम बढ़ाया जाए? आज की इस खबर में हम आपको रोजाना के पैसे बचत करने के कुछ टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

इन आदतों से बचें, वरना सेविंग सपना बन जाएगी

बिना बजट के खर्च करना

बिना प्लानिंग के खर्च करना ऐसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना—अंजाम? ज्यादा खर्च और कम बचत। हर महीने की शुरुआत में एक बजट बनाएं और उसे फॉलो करें।

जरूरत से ज्यादा खर्च करना

सेल और डिस्काउंट के चक्कर में कई बार हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं होती। अगली बार कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछें—₹क्या मैं इसके बिना नहीं रह सकता?₹ अगर जवाब 'हां' है, तो इसे छोड़ दें।

क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल

क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना आसान लगता है, लेकिन यह खर्च की एक ऐसी लत बन सकती है, जिससे उबरना मुश्किल हो जाता है। ज्यादा ब्याज और ईएमआई का बोझ ना बढ़ाएं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल केवल जरूरत के समय करें।

छोटे खर्चों को नजरअंदाज करना

एक दिन की महंगी कॉफी, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बार-बार ऑनलाइन शॉपिंग—ये छोटे खर्च मिलकर बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इन खर्चों पर नजर रखें और गैर-जरूरी चीजों को छोड़ने की आदत डालें।

इन्वेस्टमेंट न करना

सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं, उसे सही जगह निवेश भी करना जरूरी है। म्यूचुअल फंड, एफडी, या एसआईपी जैसी योजनाओं में निवेश करें, ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे।

होली पर घर आए मेहमानों के लिए बनाएं टेस्टी कद्दू की बर्फी

होली का त्योहार पूरे देश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसे में इस दिन घरों में मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है। होली पर घर आए मेहमानों के लिए अगर आप कुछ बेहतर और यूनिक बनाने का सोच रहे हैं तो आप कद्दू की बर्फी को बना सकते हैं। कद्दू की बर्फी को दूध, खोया और चीनी के साथ तैयार किया जाता है। यह खाने में काफी टेस्टी लगता है। इस लेख में हम आपको हलवाई स्टाइल में कद्दू की बर्फी बनाने के बारे में बताएंगे।

कद्दू की बर्फी बनाने की सामग्री

500 ग्राम कद्दू
एक कप खोया
आधा कप दूध
200 ग्राम चीनी
दो चम्मच घी
ड्राई फ्रूट्स

कद्दू की बर्फी के लिए तैयार करें मिश्रण

कद्दू की बर्फी को बनाने के लिए आप सबसे पहले कद्दू को सही से काट लें और इसको कद्दूकस कर लें। अब आप एक कढ़ाई में घी को गर्म करें और इसको डालें। आप इसको सात से आठ मिनट तक इसको चलाते रहें, जिससे यह नरम हो जाए। जब यह सही से पक जाए तो इसमें खोया को डालें और चलाते रहें। कुछ समय के बाद आप इसमें चीनी को डालें और मिलाएं। अब आप इसमें इलायची को पाउडर करें और साथ में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डालें। जब इन सभी का मिश्रण कढ़ाई छोड़ने लगे तब आप गैस को बंद कर दें।

कद्दू की बर्फी कैसे बनाएं?

कद्दू की बर्फी को बनाने के लिए आप इस मिश्रण को एक थाली में निकला लें और इसको समान रूप से फैलाएं। हालांकि, इस मिश्रण को थाली में डालने से पहले उसमें घी लगाना नहीं भूले। इससे मिश्रण थाली में नहीं पकड़ेगा। कुछ समय तक ठंडा होने के बाद आप अपनी पसंदीदा शेप में काट लें। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में तीन से चार दिन तक रख सकते हैं।

घर में तवे पर आसानी से बनाएं कुलचा

छोले-कुलचे अधिकतर भारतीय लोगों को पसंद होते हैं। हालांकि, बाहर इन्हें किस तरह बनाया गया है या बनाते समय हाइजीन का ख्याल रखा गया है या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में आप चाहें तो आज घर पर ही बाजार जैसे सॉफ्ट और टेस्टी कुलचे बनाकर खा सकते हैं।

चाहिए होंगी ये चीजें

2 कप आटा
2 बड़े चम्मच तेल
1 चम्मच बेकिंग पाउडर
4 बड़े चम्मच दही
आवश्यकतानुसार पानी
1/2 कप उबले मसले हुए आलू
200 ग्राम पनीर
2 बड़े चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती
2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक
2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च
1 चम्मच भुना हुआ जीरा
1 चम्मच कुटे हुए धनिये के बीज
नमक स्वाद अनुसार
1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और
आवश्यकतानुसार घी

कैसे बनाएं कुलचा?

इसके लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में आटा लें और इसमें नमक, दही, बेकिंग पाउडर और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार कर लें।

अब, आटे में 2 बड़े चम्मच तेल डालें और अच्छी तरह गूंद लें।

आटे को एक घंटे के लिए ढककर रख दें और तब तक स्टफिंग तैयार कर लें।

इसके लिए एक बाउल में उबले हुए आलू में पनीर को कद्दूकर कर डालें।

अब, इसमें बारीक कटी प्याज, हरा धनिया, 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच कुटे हुए धनिये के बीज, नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें।

अब, ढककर रखे हुए आटे से छोटी-छोटी लोई तैयार कर लें।प्रत्येक आटे की लोई में स्टफिंग भरें और सील कर दें। अब, लोई को बेलन की मदद से हल्के हाथों से बेलें।कुलचे के ऊपर ब्रश की मदद से थोड़ा पानी लगाएं और कलौंजी और कटी हुई धनिया पत्ती छिड़कें।अब, एक तवा गर्म करें और इसके ऊपर 1/4 कप पानी डाल लें।

पानी डालते ही तवे के ऊपर कुल्चा रखें और तवे को तुरंत ढक दें।कुलचे को तब तक पकने दें जब तक पानी सूख न जाए और निचला भाग सुनहरा न हो जाए।इसके बाद कुलचे के ऊपर घी लगाएं, पलटें और भूरा रंग आने तक पकाएं।

इतना करते ही आपका स्वाद में लाजवाब कुलचा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे गर्म-गर्म खा सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

तेलंगाना एमएलसी चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से मोदी खुश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तेलंगाना एमएलसी चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने एमएलसी चुनावों में भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने जनता जनार्दन के बीच कड़ी मेहनत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की भी सराहना की। तेलंगाना में भाजपा ने विधान परिषद (एमएलसी) की तीन में से दो सीटें जीती हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एमएलसी चुनावों में तेलंगाना भाजपा को इस तरह के अभूतपूर्व समर्थन के लिए मैं तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई। उन्होंने कहा कि मुझे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जो लोगों के बीच कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले तेलंगाना विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। एक अन्य शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ था।

औरंगजेब विवाद की चुनावी राज्य बिहार में भी एंट्री

पटना। महाराष्ट्र के बाद चुनावी राज्य बिहार में भी औरंगजेब विवाद की एंट्री हो चुकी है। सपा विधायक अबू आजमी के बाद बिहार में जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने भी औरंगजेब के समर्थन में बयान दिया है जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि औरंगजेब को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है। इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और वह उतना क्रूर नहीं था जितना उसे दिखाया जाता है; एक लॉबी है जो उन्हें क्रूर दिखाने की कोशिश कर रही है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने कहा कि यह एक अकादमिक चर्चा है और इस पर संसद या राजनीतिक रैली में चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए, अकादमिक चर्चा को अकादमिक ही रहने दिया जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि एक राजनीतिक दल औरंगजेब के खिलाफ इस तरह की गलत सूचना से क्या हासिल करना चाहता है।

औरंगजेब विवाद पर सीएम फडणवीस की दो टूक

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को गिरफ्तार किया जाएगा। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा विधायक को हिरासत में लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करते हुए दावा किया कि उसके शासन के दौरान भारत की सीमाएँ अफगानिस्तान और बर्मा (म्यांमार) तक फैली हुई थीं। इस बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है और महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है। आज़मी की गिरफ्तारी की स्थिति के बारे में अंबादास दानवे की पूछताछ के जवाब में, फडणवीस ने सवाल किया कि ठाकरे की शिवसेना ने कथित तौर पर शिवाजी महाराज का अपमान करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध क्यों नहीं किया।

जो संभाजी का अपमान करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं : एकनाथ शिंदे

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सपा विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। शिंदे ने संवाददाताओं से कहा, महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगा। यह तो केवल पहला कदम है। उन्हें सिर्फ यह संकेत दिया गया है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो महाराष्ट्र उन्हें माफ नहीं करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुगल बादशाह औरंगजेब पर अपनी टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को बुधवार को मौजूदा बजट सत्र की पूरी अवधि के लिए निलंबित कर दिया। आजमी की टिप्पणी के खिलाफ बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया था।

बिहार के युवाओं के लिए तेजस्वी ने बताई प्राथमिकताएं

पटना। राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के युवाओं के लिए अपना दृष्टिकोण जनता के सामने रखा है। तेजस्वी यादव ने युवा आयोग की स्थापना, नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने वाली अधिवास नीति, सरकारी नौकरी के फॉर्म की फीस माफ करना और परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के यात्रा व्यय को वहन करने की जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के युवाओं को अब 75 साल का सीएम नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, कल युवा चौपाल के दौरान हमने कहा था कि जब देश में नौकरियों और सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, तो क्या देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले बिहार के मुख्यमंत्री की आयु 75 वर्ष होनी चाहिए? बिहार के युवा अब जनता द्वारा नकारे गए अस्वस्थ सरकार के 75 वर्षीय मुख्यमंत्री को ढोना नहीं चाहते हैं।

विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक पर भारत ने ब्रिटिश सरकार को घेरा

■ **खालिस्तान तत्व आखिर एस जयशंकर की गाड़ी के पास तक कैसे पहुँच गये?**

नईदिल्ली। ब्रिटेन में खालिस्तानी तत्वों का हौसला बढ़ता ही जा रहा है। अक्सर लंदन से इस तरह की खबरें मिलती हैं कि खालिस्तानी तत्वों ने भारतीय उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया, भारतीय उच्चायोग पर हमला किया, भारतीय उच्चायुक्त के साथ बुरा बर्ताव किया आदि आदि। लेकिन अब आईएसआई के पैसे पर पलने वाले इन खालिस्तानी तत्वों का हौसला इतना बढ़ गया कि उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के सामने ही विरोध प्रदर्शन कर दिया और उनकी गाड़ी के आगे तक पहुँच कर उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। यह सही है कि सुरक्षा बलों ने तुरंत ही खालिस्तानी उग्रवादियों को धकेल दिया लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या ब्रिटिश एजेंसियों को इस बात की खबर नहीं थी कि एक कार्यक्रम में भारतीय विदेश मंत्री शिरकत कर रहे हैं और वहां बाहर जमा हो रहे उपद्रवी उनकी जान के लिए खतरा बन सकते हैं?

हम आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय छह दिवसीय ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर हैं। बुधवार को उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की और उसके बाद लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस में भारत का उदय और विश्व में भूमिका विषय पर आयोजित चर्चा में भाग लिया। जब वह बाहर निकल रहे थे तो खालिस्तानी तत्वों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और भारत विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान विदेश मंत्री पर हमले की कोशिश भी की गयी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक प्रदर्शनकारी जयशंकर की गाड़ी के आगे आकर तिरंगा झंडा फाड़ने लगा। इस हरकत को देखने के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और गाड़ी से दूर ले गए। वहीं, एक तरफ कुछ खालिस्तान समर्थक अपने हाथों में खालिस्तान का झंडा लेकर नारेबाजी कर रहे थे। यह सारा वाकया देखकर सवाल उठ रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों होने दिया गया? भारत सरकार ने इस मुद्दे को बड़ी प्रखरता के साथ ब्रिटेन के समक्ष उठाया है।

हम आपको बता दें कि भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी उल्लंघन की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हम चरमपंथियों के एक छोटे समूह की उकसावे की गतिविधियों की निंदा करते हैं। जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी उल्लंघन पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम कुछ तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए जाने की निंदा करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ''हमने विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा संबंधी चूक की घटना के फुटेज देखे हैं।'' उन्होंने कहा, ''हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह की, उकसावे वाली गतिविधियों की निंदा करते हैं।'' जायसवाल ने कहा, ''हम ऐसे तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए जाने की निंदा करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसे मामलों में मेजबान सरकार अपने कूटनीतिक दायित्वों का पूरी तरह से पालन करेगी।''

सभ्यताएं संवाद करती हैं, संघर्ष नहीं: संजय द्विवेदी

भोपाल। भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी का कहना है कि संवाद से दुनिया की हर समस्या का समाधान हो सकता है। जो लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ाई के बजाए संवाद पर आना चाहिए, क्योंकि सभ्यताएं संवाद करती हैं, संघर्ष नहीं। वे राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस,(आरजेएस पीबीएच) के आनलाईन संवाद कार्यक्रम को अध्यक्ष की आसंदी से संबोधित कर रहे थे। 'सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका' विषय पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में लंदन के प्रवासी भारतीय लेखक नितिन मेहता, द टेंपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन के महासचिव डा. ए के मर्चेंट, राम जानकी संस्थान के संस्थापक उदय कुमार मन्ना ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

प्रो. द्विवेदी ने कहा कि मीडिया का भारतीयकरण आवश्यक है, जिससे वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः (सभी सुखी हों) जैसे भारतीय मूल्यों की स्थापना संभव हो सके। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने अपने सकारात्मक योगदान से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि भारतवंशियों द्वारा की गयी पत्रकारिता ने भी वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संचार किया है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन के महासचिव डॉ. ए.के. मर्चेंट ने प्रवासी सांस्कृतिक कूटनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय प्रवासियों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि वे लगभग 136 देशों में निवास करते हैं। उन्होंने गिरमिटिया श्रम, स्वतंत्रता के बाद प्रवासन और खाड़ी देशों में प्रवासन में प्रवासी भारतीयों के इतिहास को वर्गीकृत किया तथा भारत की विदेश नीति पर इसके बढ़ते प्रभाव का उल्लेख किया। श्री मर्चेंट ने वसुधैव कुटुम्बकम के मंत्र को भारतीय विदेश नीति की आधारशिला बताया जो सम्मान, सुविधा, समृद्धि, सुरक्षा और सभ्यता के माध्यम से विश्व शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है। उन्होंने प्रौद्योगिकी में भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए इसकी आकांक्षा पर प्रकाश डाला, जिससे प्रवासी और भारतीय विदेश नीति के बीच सहजीवी संबंध स्थापित हुए हैं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रवासी लेखक नितिन मेहता (लंदन) ने सांस्कृतिक राजदूतों के रूप में भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका और एक आशावादी भारत को आकार देने में सकारात्मक मीडिया की परिवर्तनशील शक्ति पर प्रकाश डाला, जो विश्व मंच पर नेतृत्व करने के लिए तैयार है। श्री मेहता ने विश्व योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने केन्या से यूके तक की अपनी व्यक्तिगत यात्रा साझा की, जिसमें भारतीय संस्कृति की वैश्विक प्रतिध्वनि को दर्शाया गया। उन्होंने योग, ध्यान, उपवास और शाकाहार को व्यापक रूप से अपनाने पर भी जोर दिया।

आरजेएस पीबीएच क्रिएटिव टीम की प्रमुख आकांक्षा मन्ना ने लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा और राजा महेंद्र प्रताप जैसी ऐतिहासिक प्रवासी हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने विदेशी भूमि से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और सांस्कृतिक राजदूतों के रूप में प्रवासियों की दीर्घकालिक भूमिका का उदाहरण प्रस्तुत किया।

केन्या के रमेश मेहता ने सकारात्मक सोच और प्रवासी योगदान के महत्व की पुष्टि की। केन्या में नेत्र देखभाल के लिए लायंस क्लब का हवाला देते हुए उसके सामुदायिक प्रभाव का प्रमाण दिया। एक व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ते हुए, नागपुर की श्रीमती रति चौबे ने न्यूजीलैंड में अपने हालिया अनुभव को साझा किया, जहाँ उन्होंने मकर संक्रांति समारोह देखा। साधक ओमप्रकाश ने आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच की भूमिका पर जोर दिया साथ ही सत्य की सर्वोच्चता पर एक संस्कृत श्लोक का पाठ किया। कार्यक्रम का समापन वैश्विक समुदाय से वसुधैव कुटुम्बकम को अपनाने और एकता, शांति और साझा समृद्धि के भविष्य की दिशा में काम करने के सामूहिक आह्वान के साथ हुआ।

झारखंड विधानसभा में भाजपा ने सौंपी बाबूलाल मारंडी को कमान

रांची। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा में अपने विधायक दल का नेता नियुक्त किया। रांची में आयोजित एक बैठक के दौरान, मरांडी, जो झारखंड भाजपा अध्यक्ष भी हैं, को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। उनकी नियुक्ति राज्य में अपने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए पार्टी के रणनीतिक प्रयास के बीच हुई है। फैसले से पहले, भाजपा संसदीय बोर्ड ने बुधवार को पार्टी के विधायक नेता के चुनाव की निगरानी के लिए दो केंद्रीय पर्यवेक्षकों की घोषणा की थी।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव और भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के लक्ष्मण (सांसद) को इस प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। मरांडी का चयन भाजपा के झारखंड में अपनी स्थिति को मजबूत करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है क्योंकि पार्टी राज्य में आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार है। वहीं, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को नाटकीय मोड़ देखने को मिला जब भाजपा विधायकों ने विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।

पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। मरांडी ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष अनावश्यक रूप से सत्तारूढ़ दल का पक्ष ले रहे हैं, अपने सदस्यों को बोलने के लिए अधिक समय दे रहे हैं जबकि विपक्षी सदस्यों को बार-बार टोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज, जब भाजपा विधायक नीरा यादव बोल रही थीं, तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उन्हें बार-बार रोका और व्यवस्था बनाए रखने के बजाय, अध्यक्ष ने उनका बचाव किया। जब उन्होंने व्यवधानों की भरपाई के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, तो उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। यह घोर अन्याय और मनमानी है।

महाकुंभ को दहलाने की साजिश नाकाम!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान की आईएसआई से कथित संबंधों वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल के गिरफ्तार आतंकवादी ने महाकुंभ के दौरान आतंकी हमले की योजना बनाई थी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में लजार मसीह नाम के आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया।

खेल
प्रमुख समाचार

लाहौर में नहीं दुबई में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला

दुबई। रविवार, 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला लाहौर की बजाय दुबई में खेला जाएगा। इस मेगा इवेंट में भारत ने पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर फाइनल में एंट्री की। वहीं फाइनल मुकाबले के लाहौर की बजाय दुबई में होने से भारत ने पाकिस्तान का करोड़ों का नुकसान करा दिया है।

दरअसल, सुरक्षा कारणों से टीम इंडिया ने पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में पहले ही तय हो गया था कि भारतीय टीम अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी। इसके अलावा ये भी तय था कि 1 सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा। साथ ही अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो ये मैच दुबई में खेला जाएगा। अगर भारत फाइनल में नहीं पहुंचता तो ये मुकाबला लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाना था।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल का वेन्यू बदलने से पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हो गया है। चैंपियंस ट्रॉपी की 8 साल बाद वापसी हुई। आखिरी बार ये टूर्नामेंट 2017 में खेला गया था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुल 15 मुकाबले खेले जाने थे। इसके लिए 586 करोड़ रुपये का बजट था। ऐसे में हर मैच के लिए करीब 39करोड़ रुपये का बजट फिक्स था।

भारतीय टीम अब तक 4 मैच दुबई में खेल चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 156 करोड़ रुपये का नुकसान तो हो चुका है। अब भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान को एक और मैच के लिए 39 करोड़ का नुकसान होगा और पीसीबी का कुल घाटा 195 करोड़ रुपये हो जाएगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 610 अंक चढ़ा निफ्टी 22,500 के पार

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से पॉजिटिव संकेत लेते हुए घरेलू शेयर बाजार गुरुवार (6 मार्च) को जोरदार तेजी के साथ बंद हुए। शुरुआती कारोबार में अस्थिरता के बावजूद दोपहर के सेशन में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी आई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के मेक्सिको और कनाडा के ऑटोमोबाइल पर टैरिफ को एक महीने के लिए टालने से वैश्विक बाजारों ने आज राहत की सांस ली है। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज 500 से ज्यादा अंक चढ़कर 74,308 पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार में यह लाल निशान में फिसल गया था। अंत में सेंसेक्स 609.86 अंक या 0.83% की तेजी के साथ 74,340.09 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी मजबूती के साथ 22,476 पर ओपन हुआ। अंत में निफ्टी 207.40 अंक या 0.93% की बढ़त लेकर 22,544.70 पर क्लोज हुआ।

डिफेंस डील्स पर सरकार की बड़ी तैयारी!

नईदिल्ली। रक्षा मंत्रालय अब हथियारों और रक्षा प्रणालियों की खरीद में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का विस्तार करने जा रहा है। इससे प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को ज्यादा अवसर मिलने की संभावना है। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने सूत्रों को बताया कि यह निर्णय उन उपकरणों के लिए लिया गया है, जिनके निर्माण की क्षमता भारतीय निजी उद्योग ने स्थापित कर ली है। सरकार के इस कदम से प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ेगी और रक्षा उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत नॉमिनेशन प्रक्रिया से हटकर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। नॉमिनेशन प्रक्रिया में रक्षा खरीद अनुबंधों को बिना टेंडरिंग प्रक्रिया के सीधे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दिया जाता था।

टेस्ला का भारत में पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा

नईदिल्ली। ईलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इंक ने भारत में अपना पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में लीज पर लिया है। यह शोरूम रू. 881 प्रति वर्ग फुट के रिकॉर्ड किराये पर लीज पर दिया गया है, जो देश में अब तक का सबसे महंगा लीज रेंटल माना जा रहा है। कंपनी ने 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, ग्राउंड फ्लोर, यूनिट जी-1बी के लिए लीज एग्रीमेंट साइन किया है। यह इमारत बीकेसी के प्रमुख बिजनेस हब में स्थित है और हाई-एंड ऑफिस बिल्डिंग के रूप में जानी जाती है। 27 फरवरी 2025 को फाइनल हुई इस डील के तहत टेस्ला इंडिया ने रू. 2.11 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है। कंपनी को हर महीने रू. 35.26 लाख किराया देना होगा, जिसमें सालाना 5% बढ़ोतरी होगी। यह लीज 4,003 वर्ग फुट के ऑफिस स्पेस के लिए है, जिसका किराया रू. 881 प्रति वर्ग फुट तय किया गया है।

रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी दे रही तगड़ा डिविडेंड

नईदिल्ली। रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाली मल्टी-ब्रांड फुटवियर रिटेल कंपनी मेट्रो ब्रांड्स ने अपने शेयरहोल्डर्स को डबल तोहफा दे रही है। दरअसल कंपनी अंतरिम डिविडेंड के साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्पेशल डिविडेंड भी दे रही है। दिवंगत दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास दिसंबर 2024 के अंत में कंपनी में 4.8 फीसदी हिस्सेदारी थी। मेट्रो ब्रांड्स ने एक एक्सचेंज फाईलिंग में कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड और 14.50 रुपये प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। इस तरह डिविडेंड की टोटल अमाउंट 17.50 रुपये शेयर बनती है। मेट्रो ब्रांड्स ने अपने दोनों डिविडेंड के लिए 7 मार्च, 2025 को रिकॉर्ड तिथि तय की है।

शहरों के लिए बजट की पाई-पाई का हो इस्तेमाल

देवार्पिता रॉय

इस साल बजट में हुए आवंटन पर चर्चा के दौर लगभग थम गए हैं। ऐसे में यह पड़ताल होनी चाहिए कि सरकार के तीनों स्तर और दूसरी संबंधित एजेंसियां कौन से उपाय करें, जिनसे भारत के शहरों के लिए आवंटित एक-एक पैसे का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।

पिछले कुछ साल की तरह इस बार भी शहरी मंत्रालय के लिए आवंटन कुल बजट का लगभग 2 फीसदी रहा है। लेकिन शहरी उप-क्षेत्रों और कार्यक्रमों में इसका वितरण बदल गया है। शहरी आवास की हिस्सेदारी घटी है और नई योजनाओं की शुरुआत धीमी गति से हो रही है। उनके बजाय पिछली योजनाओं के तहत मकानों का निर्माण पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। परिवहन विशेषकर मेट्रो रेल और बुनियादी सेवा क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ा है क्योंकि ये योजनाएं पहले जैसी गति से चल रही हैं। स्मार्ट सिटी अभियान ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है मगर अर्बन चैलेंज फंड जोड़ दिया गया है, जिसका मकसद शहरों को नया रूप देना है।

शहरी आवास से शुरू करें तो जिन तीन योजनाओं के लिए सब्सिडी दी गई है, वे हैं 2015 से चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी (पीएमएवाई-यू) चरण 1, पीएमएवाई-यू चरण 2 और पिछले साल घोषित औद्योगिक आवासीय योजनाएं। शहरी आवास का तीन-चौथाई से अधिक बजट पीएमएवाई-यू के पहले चरण के तहत आवास निर्माण पर सब्सिडी देने के लिए है। इस चरण में 32 लाख आवास अभी बनने हैं, इसलिए नई आवासीय योजनाएं शुरू करने से पहले उनके निर्माण को प्राथमिकता देना समझदारी की बात है।

इस बजट में बिल्कुल ऐसा ही किया गया

है। जो मकान बनने हैं, वे ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों के लिए हैं, जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपये या उससे कम है। इन मकानों पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे परिवार का निर्माण पर आने वाला खर्च कम हो जाता है। इस सब्सिडी में 2015 से कोई बदलाव नहीं किया गया है मगर मकान बनाने का खर्च बढ़ गया है और लाभार्थियों को इसमें ज्यादा रकम लगानी पड़ रही है। इसलिए इन गरीब परिवारों को पहले की तुलना में अधिक धन की दरकार हो जाती है। उनके लिए किफायती आवास ऋण की उपलब्धता बढ़ाना इसके समाधान का एक तरीका है। पीएमएवाई-यू के पहले चरण पर हुए शोध में भी बताया गया है कि इस तरह का कर्ज नहीं मिलना ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए पीएमएवाई-यू चरण 1 के लाभार्थियों को पहले के मुकाबले अधिक आसानी से किफायती आवास ऋण उपलब्ध कराना जरूरी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के दूसरे चरण के लिए आवंटन केवल आवास ऋण के ब्याज पर सब्सिडी देने के मकसद से किया गया है। इससे परिवारों की मासिक किस्त कम हो जाती है। इसमें 70 फीसदी आवंटन ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग (सालाना आमदनी 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच) के लिए है। बाकी रकम मध्यम आय वर्ग (सालाना आमदनी 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक) के लिए है।

सीएसईपी में किए गए शोध बताते हैं कि पीएमएवाई-यू के पहले चरण में ऐसी ही आवास ऋण सब्सिडी योजना के तहत केवल 21 फीसदी लाभार्थी ईडब्ल्यूएस वर्ग से थे। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस योजना के दूसरे चरण में लाभ पाने वाले ईडब्ल्यूएस परिवारों का अनुपात पहले चरण से ज्यादा हो। यह भी जरूरी है कि दूसरे चरण में ऐसे परिवारों को ज्यादा आसानी के साथ वित्तीय संस्थाओं से आवास ऋण मिले।

औद्योगिक आवास के लिए आवंटन के तहत ऐसे मकान बनाने (उद्योगों के साथ मिलकर) के लिए सब्सिडी दी जाएगी, जो औद्योगिक कामगारों को किराये पर मिल सकें। इससे औद्योगिक वृद्धि तथा रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा और किराये के लिए अधिक मकान भी तैयार हो सकते हैं।

149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के साथ बना नया कीर्तिमान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान खरीदी के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं. राज्य सरकार ने किसानों से 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए गए, जिनका परिणाम अभूतपूर्व रहा है.

धान खरीदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड: धान उत्पादन में अग्रणी छत्तीसगढ़ ने इस बार ऐतिहासिक रूप से अधिकतम मात्रा में धान खरीदी की है. राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई. इस दौरान कुल 24.5 लाख किसानों ने अपनी उपज सरकार को बेची. धान खरीदी के इस नए कीर्तिमान के पीछे विष्णु देव साय सरकार की पारदर्शी नीतियां और किसान-हितैषी योजनाएं प्रमुख रूप से जिम्मेदार मानी जा रही हैं. सरकार ने न केवल रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की, बल्कि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया और फसल को सुरक्षित रखने के लिए उन्नत व्यवस्थाएं भी लागू कीं.

धान खरीदी में पारदर्शिता और डिजिटल मॉनिटरिंग: राज्य सरकार ने इस बार धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटलाइज्ड किया, जिससे किसानों को न्यूनतम परेशानी हुई. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए किसानों को धान बेचने की सुविधा दी गई, जिससे किसी भी तरह की बिचौलिया व्यवस्था समाप्त हो गई.सरकार ने 1700 से अधिक खरीद केंद्रों की स्थापना की, जहां किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य प्रदान किया गया.

अर्थव्यवस्था को मिला बढ़ावा: धान खरीदी के बाद सरकार ने यह

विष्णु देव साय की सरकार में छत्तीसगढ़ के किसान हो रहे मालामाल,

सुनिश्चित किया कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान बिना किसी देरी के मिले. अब तक सरकार ने 34,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है..इसके अलावा, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ ही कस्टम मिलिंग प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि प्रदेश के नागरिकों को उचित मूल्य पर चावल उपलब्ध कराया जा सके और राज्य की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके.

साय सरकार की किसान-हितैषी नीतियां: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस रिकॉर्ड धान खरीदी पर कहा, छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. हमने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को लागू करते हुए किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने का कार्य किया है. यह किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि हम इस बार ऐतिहासिक धान खरीदी कर सके.卐

राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई अहम कदम उठाए हैं:-

धान बेचने वाले किसानों को अतिरिक्त बोनस राशि दी गई.

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया, जिससे धान उत्पादन में वृद्धि हुई.

खाद-बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई, जिससे किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया गया.

नया रिकॉर्ड बनने से किसानों में उत्साह: धान खरीदी में नया रिकॉर्ड बनने के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों में खुशी की लहर है. रायपुर जिले के किसान रामप्रसाद साहू का कहना है, 卐पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें धान का पूरा पैसा समय पर मिल गया. पहले कई बार भुगतान में देरी होती थी, लेकिन इस बार सरकार ने ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. इसी तरह, दुर्ग के किसान गोविंद पटेल ने बताया, धान खरीदी केंद्रों पर इस बार कोई अव्यवस्था नहीं थी.सरकार ने सही समय पर बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं हुई.

देश का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य: इस रिकॉर्ड धान खरीदी के साथ ही छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य बन गया है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य की जलवायु, उन्नत कृषि तकनीक और सरकारी योजनाओं की वजह से धान उत्पादन लगातार बढ़ रहा है.विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार हुई रिकॉर्ड धान खरीदी से राज्य की जीडीपी में 3त्न तक की वृद्धि होने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान खरीदी का नया कीर्तिमान बना है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर सरकार ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और राज्य ने धान उत्पादन के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है.

सरकार की पारदर्शी नीतियां, डिजिटल प्रक्रिया, समय पर भुगतान और किसानों के प्रति प्रतिबद्धता के चलते यह उपलब्धि संभव हो पाई है. आने वाले वर्षों में भी छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में इसी तरह काम करती रहेगी, जिससे राज्य की कृषि और अधिक उन्नति कर सके.

171 औद्योगिक दुर्घटनाएं, 124 श्रमिकों की मौत उद्योग मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी

रायपुर । प्रदेश में औद्योगिक सुरक्षा और दुर्घटनाओं को लेकर विधानसभा में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत द्वारा औद्योगिक दुर्घटनाओं में हुई जान-माल की क्षति और मुआवजे को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने आंकड़े पेश किए।

दुर्घटनाओं का आंकड़ा और क्षति: मंत्री ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 तक प्रदेश में कुल 171 औद्योगिक दुर्घटनाएं हुईं। इन घटनाओं में 124 श्रमिकों की मृत्यु हुई और 86 श्रमिक घायल हुए।

मुआवजा और पुनर्वास स्थिति: मृत श्रमिकों के आश्रितों को कुल 17,23,68,454 की मुआवजा राशि प्रदान की गई। घायल श्रमिकों को 60,32,342 की मुआवजा राशि दी गई।

मृतकों के परिजनों के पुनर्वास को लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जांच और औद्योगिक सुरक्षा उपाय: सभी 171 औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच कराई गई। कारखाना अधिनियम के उल्लंघन में 191 औद्योगिक इकाइयों को दोषी पाया गया।औद्योगिक सुरक्षा को लेकर यह आंकड़े गंभीर चिंताओं को जन्म देते हैं। विपक्ष ने सरकार से सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

भूपेश ने विधानसभा में सरकार पर साधा निशाना

रायपुर । विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आचार संहिता के उल्लंघन और मुख्यमंत्री की विधानसभा में अनुपस्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। भूपेश बघेल ने कहा, अगर कोई आचार संहिता को लेकर सवाल पूछे, तो उसे जेल भेज दिया जाता है। अगर कोई सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाए, तो उसकी जान चली जाती है। लेकिन अब जब आचार संहिता लागू है, तब खुद सरकार के मंत्री और अधिकारी चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं। यह नियमों का खुला उल्लंघन है।

उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता को जवाबदेही चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री खुद ही सवालों से बचते नजर आते हैं। बघेल ने कहा, आज मुख्यमंत्री को सदन में रहना चाहिए था, लेकिन वे अनुपस्थित हैं। क्या यही लोकतंत्र का सम्मान है?पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब वे सत्ता में थे, तब भी सवालों का जवाब देना अनिवार्य था। उन्होंने वित्त मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तर कोई भी मंत्री दे सकता है।

यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान पर परिवहन विभाग की बैठक

रायपुर। ई - रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान से जुड़े विषयों पर परिवहन सचिव सह आयुक्त श्री एस.प्रकाश की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर भी उपस्थित थे।

ई - रिक्शा एवं ऑटो की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के उपायों पर बैठक में विचार - विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि जिलेवार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ई-रिक्शा (गुड्स एवं पैसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 13374, बिलासपुर 4493, दुर्ग 4038, अंबिकापुर 1311, जगदलपुर 41, इसी प्रकार पंजीकृत ऑटो (गुड्स एवं पेसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 20306, बिलासपुर 14867, दुर्ग 9602, अम्बिकापुर 4429, जगदलपुर 3431 है, इस संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। बिना मॉनिटरिंग एवं रेगुलेशन के इन पर नियंत्रण की समस्या पर चर्चा की गई।

जिला प्रशासन रायपुर ने जोनवार योजना बनाई: बैठक में रायपुर जिला प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा एवं ऑटो के सुगम व्यवस्थित परिचालन हेतु निर्मित जोनवार योजना के बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा रायपुर शहर को मुख्य रूप से 05 जोनों में विभक्त कर योजना बनाई गई है। बैठक में ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त राज्य शासन एवं जिला प्रशासन को प्राप्त शक्तियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उपस्थित जिलों के अधिकारियों से क्रमशः उनके जिलों में ई-रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली गई।

कांग्रेस ने किया महिला पत्रकारों का "कलम वीरांगना सम्मान"

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाली महिला पत्रकारों का सम्मान कांग्रेस संचार विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, कांग्रेस के राष्ट्रीय सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने शाल एवं मोमेंटो देकर महिला पत्रकार बहनों का सम्मान किया।

इस अवसर पर उद्बोधन देते हुये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मीडिया के क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को काम करते हुए देख कर सुखद अनुभूति होती है। पहले के जमाने में प्रिंट मीडिया में पूरे रायपुर में तीन-चार महिला पत्रकार ही दिखती थी। यह बड़ी उपलब्धि है कि आज रिपोर्टिंग और एंकरिंग दोनों ही स्थानों पर महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है। आज की नारी सशक्त हो गयी है। कांग्रेस पार्टी लगातार तीन वर्षों से महिला पत्रकारों का सम्मान करते आ रही है। आप सबका यहां आना कांग्रेस के लिए गौरव का क्षण है। आजादी के समय से पत्रकारिता और पत्रकारों की अहम भूमिका रही है। पहले कहा जाता था "खीचों न कमानो को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।" आप सबका देश के नवनिर्माण लोकतंत्र को बचाने में बड़ी भूमिका है। महिला पत्रकारों के सम्मान की परंपरा आगे बढ़ाने के लिए संचार विभाग को बधाई।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना महिलाओं के लिये बड़ी चुनौती है आप सब इस चुनौती को बखूबी निभा रही है। आम सबको सम्मानित करके हमें खुशी हो रही है। विपक्ष के रूप में हमें मीडिया से विशेष संरक्षण की अपेक्षा रहती है। महिला पत्रकार देश के लोकतंत्र को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आम आदमी की आवाज पत्रकार होते है, आपका काम कठिन है, घर एवं काम में सामंजस्य बना कर जनता की सेवा करना महत्वपूर्ण है। हम सब आप को सेल्यूट करते है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

आईएएस महादेव कावरे ने केटीयू के कुलपति का संभाला पदभार

रायपुर. छत्तीसगढ़ के द्बस्र महादेव कावरे ने मीडिया गुरुकुल कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में कुलपति पद का पदभार संभाल लिया है. उन्होंने कुलपति पदभार ग्रहण करते ही विश्वविद्यालय प्रशासन को अकादमिक और शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने विश्वविद्यालय में अध्यनरत छात्र-छात्राओं की समग्र उन्नति एवं उनकी प्रतिभा को निखारने, अध्ययन विभाग में नियमित अध्यापन के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पत्रकारिता, मीडिया शिक्षा और मीडिया इंडस्ट्रीज के साथ लिंकेज कार्यक्रम करने और अकादमिक करिकुलम को प्राथमिकता के साथ बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के भी निर्देश दिए हैं.

रायपुर नगर निगम सभापति का चुनाव आज

रायपुर। नगर निगम सभापति का चुनाव शुक्रवार को होगा. भाजपा के सीनियर पार्षद सूर्यकांत राठौर को रायपुर नगर निगम के सभापति बनाए जा सकते हैं. चुनाव से पहले भाजपा पार्षद दल की बैठक में राठौर को सभापति प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है. सभापति के निर्विरोध निर्वाचन के आसार हैं. वजह यह है कि कांग्रेस के मात्र 6 पार्षद ही चुनकर आए हैं, जबकि भाजपा पार्षदों की संख्या 60 है. चार निर्दलीय पार्षदों का झुकाव भी भाजपा की तरफ है. दूसरी तरफ सभापति के चयन के लिए भाजपा ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरम लाल कौशिक को पर्यवेक्षक बनाया है.सूत्रों के मुताबिक, तीन नामों का पैनल बनाया गया है. इसमें सूर्यकांत राठौर, मनोज वर्मा और सरिता आकाश दुबे का नाम है. इसमें से राठौर के नाम पर मुहर लग सकती है. भाजपा पार्षद दल की सुबह 11 बजे बैठक में पर्यवेक्षक धरमलाल कौशिक प्रत्याशी के नाम का अधिकृत तौर पर ऐलान करेंगे, फिर इसके बाद नगर निगम सभागार में बैठक होगी, जिसमें फिर सरकारी तौर पर चुनाव की प्रक्रिया होगी.

राज्य स्तरीय महिला मड़ई को मिल रहा अच्छा प्रतिसाद

रायपुर । रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सशक्त महिला समृद्ध महिला थीम पर आयोजित महिला मड़ई को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 4 मार्च से चल रहे महिला मड़ई में राज्य के सभी 33 जिलों से 87 महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा विक्रय के लिए स्टाल लगाया गया है।जिसमें प्रमुख रूप से रायगढ़ से एकताल बेलमेटल, सूरजपुर से समूह द्वारा निर्मित गुड़ की सामग्री, बस्तर से बेल मेटल, जांजगीर चांपा और सक्ति से कोसा, हैंडलूम सिल्क साड़ी, गरियाबंद से पैरा आर्ट, जशपुर से टोकनी,महुआ से उत्पादित सामग्री, बिलासपुर से श्रृंगार वस्त्र की सामग्री, बलरामपुर और सूरजपुर से उत्पादित सुगंधित चावल के स्टॉल में लोगों की ख़ासकर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। महिला मड़ई की नोडल अधिकारी ने बताया कि महिला स्व-सहायता समूहों ने 50 हजार रुपए से अधिक के सामग्रियों का विक्रय कर लिया है, मड़ई में 8 मार्च महिला दिवस के दिन तक और भी अधिक सामग्रियों के विक्रय होने की संभावना है ।महिला मड़ई में लगाए गए 87 स्टॉलों बिक्री-सह प्रदर्शनी का अवलोकन दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। मड़ई में सेल्फी जोन बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाया गया है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झूले एवं खेल-खिलौने की व्यवस्था की गई है।

महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत किए जाने का आदेश जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत किए जाने की अपनी घोषणा को पूरा करके राज्य के लाखों शासकीय सेवकों को होली पर्व से पूर्व सौगात दी है। यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली

छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में शासकीय सेवकों को 53 प्रतिशत डीए किए जाने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा के परिपालन में शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने का आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके 53 प्रतिशत किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अब उन्हें 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अब उन्हें 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। यह वृद्धि 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगी और इसका भुगतान मार्च 2025 के वेतन के साथ अप्रैल माह में किया जाएगा।

जय व्यापार पैनल का प्रचार पूरे छत्तीसगढ़ में जोर पकड़ा

रायपुर। जय व्यापार पैनल से जितेन्द्र दोशी , विक्रम सिंहदेव एवं परमानन्द जैन ने बताया कि छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर जय व्यापार पैनल पूरी सक्रियता के साथ पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान में जुटा हुआ है और एकतरफा मिल रहे समर्थन से खासे उत्साहित भी हैं। जय व्यापार पैनल के इकाई के प्रभारी द्वय महेश जेठानी, अवनीत सिंह के साथ नरेश माखीजा, विजय शादीजा एवं टीम के साथ आज कोरबा के सदस्यों से मुलाकात की। चर्चाओं के साथ-साथ भविष्य में व्यापार को और कैसे नई उंचाई पर ले जाने हेतु अपने विचारो की प्रस्तुति दी। साथ ही साथ आनें वाले चुनाव में जय व्यापार पैनल को पुनः पूर्ण बहुमत प्रदान करनें हेतु निवेदन किया । सम्पर्क यात्रा के दौरान प्रत्येक इकाई द्वारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया है। जनसम्पर्क के दौरान मिल रहे आत्मीयता एवं सम्मान से पूरी टीम अभिभूत है। पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक जीत होने वाली है। कोरबा जय व्यापार पैनल के पदाधिकारी रामसेवक अग्रवाल, परसराम रामानी, जयंत कुमार अग्रवाल, रवि लालवानी, प्रभु अग्रवाल शामिल रहे।

उद्योग स्थापना के लिए 2024 से जनवरी 2025 तक नहीं हुआ एक भी एमओयू: साव

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने राज्य सरकार को उद्योग स्थान को लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन को घेरा। मंत्री देवांगन ने प्रश्नकाल के दौरान लिखित उत्तर में बताया कि प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कोई एमओयू नहीं किए गए हैं।

महंत ने उद्योग मंत्री से पूछा कि प्रदेश में जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक किस-किस प्रकार के कितने उद्योगों की स्थापना हेतु शासन द्वारा किन-किन उद्योगपतियों/संस्थाओं के साथ कितनी-कितनी राशि के एम.ओ.यू. किए गए हैं? एम.ओ.यू. के अनुसार कितने उद्योगों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया है? उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश में उद्योग स्थापना हेतु

जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कोई एमओयू नहीं किए गए हैं। राज्य में औद्योगिक निवेश की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए रूपये 100 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश के प्राप्त होने वाले अभिरूचि प्रस्तावों पर एमओयू निष्पादन के स्थान पर इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट संबंधी पत्र जारी किये जा रहे हैं। प्रदेश में जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कुल 31 इकाइयों को उनके निवेश अभिरूचि प्रस्तावों पर इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किए गए है।

महंत ने फिर पूछा कि उद्योगों की स्थापना प्रदेश के किन जिले, ब्लाक, ग्राम पंचायतों में की जानी है तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को कितने कुशल एवं अकुशल रोजगार प्राप्त हुआ अथवा होगा? मंत्री देवांगन ने बताया कि उपरोक्त निवेश प्रस्तावों में उद्योग स्थापना हेतु वर्तमान में स्थल चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन उद्योगों में कुल 22557 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत घोषित किए गए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्यम को राज्य के मूल निवासियों को स्थायी नियोजन में अकुशल कर्मचारियों/श्रमिक के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

नेता प्रतिपक्ष ने जानना चाचा कि वर्ष 2024-25 में इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का आयोजन कहां-कहां किस तिथि को किया गया? उद्योग मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का आयोजन दिनांक 23.12.2024 को नई दिल्ली एवं दिनांक 23.01.2025 को मुम्बई में किया गया।

जिला प्रशासन की तत्परता से नाबालिग बालिका का विवाह रुका, शिक्षा जारी रखने का संकल्प

रायपुर। जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग की सतर्कता से मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के ग्राम साल्हेघोरी में एक नाबालिग बालिका का विवाह रोका गया। कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जिसने समय रहते हस्तक्षेप कर इस विवाह को रोकने में सफलता हासिल की।

बाल विवाह की सूचना मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती संजुला शर्मा के मार्गदर्शन में टीम मौके पर पहुंची और हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले विवाह को स्थगित कराया। परिजनों से बातचीत में पता चला कि गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक तंगी के कारण वे बालिका का विवाह कराना

चाह रहे थे, ताकि मजदूरी के लिए अन्य राज्य पलायन कर सकें। लेकिन बालिका ने हिम्मत दिखाते हुए विवाह से इनकार कर दिया और कहा कि वह 10वीं कक्षा तक पढ़ चुकी है और आगे अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती है।

बालिका को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया, जहां समिति के सदस्य श्रीमती लक्ष्मी साहू, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती अंजुबाला शुक्ला और चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक श्री उमाशंकर कश्यप ने उसे श्रीफल, पेन और डायरी देकर सम्मानित किया। साथ ही, परिजनों को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया, ताकि वे बेटी की शिक्षा में किसी बाधा के बिना उसका भविष्य संवार सकें।गौरतलब है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह या किसी भी संकटग्रस्त बच्चे की जानकारी तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।इस घटनाक्रम से एक बार फिर साबित हुआ कि सजग प्रशासन और जागरूक समाज मिलकर बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। यह पहल न केवल बालिका को उसका अधिकार दिलाने में सफल रही।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.